RACE IAS

A Leading Institute For Civil Services Examinations

ANSWERS & EXPLANATIONS

GENERAL STUDIES (P) 2026

INDIAN ECONOMY

EXAM DATE : 27-12-2026

QUESTIONS BOOKLET NO. : 2911347505

1. Answer: (a)
Explanation:
Statements 1 and 2 are correct. The Union Budget 2025–26 targets a fiscal deficit of 4.4% of GDP, and interest payments constitute about one-fourth of total expenditure. Statement 3 is incorrect because the government's stated target is to reduce outstanding liabilities to 50% of GDP by March 2031, not 40%.

2. Answer B
- Statement 1 is correct: Stagflation is a period of rising inflation but falling output and rising unemployment. In this case, incomes shrink and yet prices rise. This is a complicated situation as it presents a dilemma for economic policy, since actions intended to lower inflation may exacerbate unemployment.
- Statement 2 is incorrect: In normal low growth situations, the government or the central bank can provide economic stimulus via higher public spending and cut interest rates. But in stagflation, when inflation is already running high, fiscal and monetary stimulus can make it worse as that puts more money in the hands of the consumer. There are no easy solutions to stagflation. Monetary policy can generally try to reduce inflation (higher interest rates) or increase economic growth (cut interest rates). Monetary policy cannot solve both inflation and recession at the same time.
- Statement 3 is correct: Stagflation can result when the economy faces a supply shock-a sudden increase or decrease in the supply of a commodity. Example-a rapid increase in the price of oil. An unfavorable situation like that tends to raise prices at the same time as it slows economic growth by making production more costly and less profitable.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

1. उत्तर: (a)
व्याख्या:
स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। यूनियन बजट 2025–26 का टारगेट GDP का 4.4% फिस्कल डेफिसिट है, और इंटरेस्ट पेमेंट कुल खर्च का लगभग एक-चौथाई है। स्टेटमेंट 3 गलत है क्योंकि सरकार का बताया गया टारगेट मार्च 2031 तक बकाया लायबिलिटी को GDP के 50% तक कम करना है, न कि 40%।

2. उत्तर B
- कथन 1 सही है: स्टैगफ्लेशन बढ़ती मुद्रास्फीति लेकिन गिरते उत्पादन और बढ़ती बेरोजगारी की अवधि है। इस मामले में, आय कम हो जाती है और फिर भी कीमतें बढ़ती हैं। यह एक जटिल स्थिति है क्योंकि यह आर्थिक नीति के लिए एक दुविधा प्रस्तुत करती है, क्योंकि मुद्रास्फीति को कम करने के उद्देश्य से की गई कार्रवाइयां बेरोजगारी को बढ़ा सकती हैं।
- कथन 2 गलत है: सामान्य कम विकास स्थितियों में, सरकार या केंद्रीय बैंक उच्च सार्वजनिक व्यय और ब्याज दरों में कटौती के माध्यम से आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। लेकिन स्टैगफ्लेशन में, जब मुद्रास्फीति पहले से ही उच्च स्तर पर चल रही है, तो राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन इसे और भी बदतर बना सकते हैं क्योंकि इससे उपभोक्ता के हाथों में अधिक पैसा आ जाता है। स्टैगफ्लेशन का कोई आसान समाधान नहीं है। मौद्रिक नीति आम तौर पर मुद्रास्फीति को कम करने (उच्च ब्याज दरें) या आर्थिक विकास बढ़ाने (ब्याज दरों में कटौती) का प्रयास कर सकती है। मौद्रिक नीति एक ही समय में मुद्रास्फीति और मंदी दोनों का समाधान नहीं कर सकती है।
- कथन 3 सही है: मुद्रास्फीतिजनित मंदी तब उत्पन्न हो सकती है जब अर्थव्यवस्था को आपूर्ति के झटके का सामना करना पड़ता है - किसी वस्तु की आपूर्ति में अचानक वृद्धि या कमी। उदाहरण-तेल की कीमत में तेजी से वृद्धि। इस तरह की प्रतिकूल स्थिति कीमतें बढ़ाने के साथ-साथ उत्पादन को अधिक महंगा और कम लाभदायक बनाकर आर्थिक विकास को धीमा कर देती है।

3. Answer B
   - Statement 1 is correct: Increased Government spending has a direct impact on the level of consumer spending in an economy. This leads to a higher demand for goods and services which eventually results in higher prices due to demand-pull inflation. The increased government spending can lead to higher growth in the short-term and also has the potential to cause inflation.
   - Statement 2 is correct: COVID-19 has disrupted supply chains around the world. A major reason for post-lockdown high inflation is supply disruptions. With the shutdown in production activities and transportation disruption, the global prices of raw materials and intermediate supplies have increased.
   - Statement 3 is incorrect: Inflation and unemployment have an inverse relationship, as represented by the Phillips curve. Low levels of unemployment correspond with higher inflation, while high unemployment corresponds with lower inflation.

4. Answer: (b)

Explanation

The Ministerial Conference meets biennially to set policy. The General Council manages daily operations, including dispute settlement. Subsidies are categorized to prevent market distortion: Agriculture uses "Boxes" (Amber is distorting, Green is allowed), while Industrial subsidies are regulated by the SCM Agreement. Statement 2 is incorrect because the AoA only applies to agricultural products, not industrial ones.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

3. उत्तर B
   - कथन 1 सही है: सरकारी खर्च में वृद्धि का अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता खर्च के स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप अंततः मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। बढ़े हुए सरकारी खर्च से अल्पावधि में उच्च विकास हो सकता है और मुद्रास्फीति बढ़ने की भी संभावना है।
   - कथन 2 सही है: COVID-19 ने दुनिया भर में आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया है। लॉकडाउन के बाद उच्च मुद्रास्फीति का एक प्रमुख कारण आपूर्ति में व्यवधान है। उत्पादन गतिविधियों में रुकावट और परिवहन व्यवधान के साथ, कच्चे माल और मध्यवर्ती आपूर्ति की वैश्विक कीमतें बढ़ गई हैं .
   - कथन 3 गलत है: मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का विपरीत संबंध है, जैसा कि फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया गया है। बेरोजगारी का निम्न स्तर उच्च मुद्रास्फीति से मेल खाता है, जबकि उच्च बेरोजगारी कम मुद्रास्फीति से मेल खाती है।

4. उत्तर: (b)

स्पष्टीकरण

मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस पॉलिसी तय करने के लिए हर दो साल में मिलती है। जनरल काउंसिल रोज़ाना के कामों को मैनेज करती है, जिसमें झगड़े निपटाने भी शामिल हैं। सब्सिडी को मार्केट में गड़बड़ी रोकने के लिए कैटेगरी में बांटा गया है: एग्रीकल्चर में "बॉक्स" का इस्तेमाल होता है (एम्बर गड़बड़ी करता है, ग्रीन अलाउड है), जबकि इंडस्ट्रियल सब्सिडी SCM एग्रीमेंट से रेगुलेट होती हैं। स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि AoA सिर्फ़ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर लागू होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर नहीं।

5. Answer C
   - Statement 1 is correct: The increasing inflation rates have negative effects on the value of a currency. The currency becomes weaker compared to other currencies. The increasing inflation also leads to a higher input costs for exports, which then makes a nation's exports less competitive in the global markets. This will widen the trade deficit and cause the currency to depreciate.
   - Statement 2 is incorrect: Monetary Policy Committee is a statutory and institutionalized framework under the Reserve Bank of India Act, 1934, for maintaining price stability, while keeping in mind the objective of growth. The MPC determines the policy interest rate required to achieve the inflation target of 4% within a band of +/- 2%.

6. Answer C
   - Statement 1 incorrect: During colonial period in India, There was not only the unilateral transfer of investible capital to Britain by the colonial state , but the unequal exchange was day by day crippling India's commerce, trade and the thriving handloom industry, too.
   - Throughout colonial rule, the economic vision that the state had was to increase India's capacity to export primary products, and increase the purchase/import of the British manufactured goods and raise revenues to meet the drain of capital as well as meet the revenue requirements of the imperial defence.
   - Statement 2 correct: Industrialisation of India was also neglected by the colonisers—the infrastructure was not built to industrialise India but to exploit its raw materials.
   - Indian capitalists who did emerge were highly dependent on British commercial capital and many sectors of the industry were dominated by British firms, e.g., shipping, banking, insurance, coal, plantation crops and jute.
   - Statement 3 incorrect: The pre-independence period was altogether a period of near stagnation showing almost no change in the structure of production or in the levels of productivity.
   - The aggregate real output during the first half of the 20th century was estimated at less than 2 percent a year or less.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations
RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

5. उत्तर C
   - कथन 1 सही है: बढ़ती मुद्रास्फीति दर का मुद्रा के मूल्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अन्य मुद्राओं की तुलना में मुद्रा कमजोर हो जाती है। बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण निर्यात के लिए इनपुट लागत भी बढ़ जाती है, जिससे देश का निर्यात वैश्विक बाजारों में कम प्रतिस्पर्धी हो जाता है। इससे व्यापार घाटा बढ़ेगा और मुद्रा का अवमूल्यन होगा।
   - कथन 2 गलत है: मौद्रिक नीति समिति विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत एक वैधानिक और संस्थागत ढांचा है। एमपीसी मुद्रास्फीति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करती है। +/- 2% के बैंड के भीतर 4% का लक्ष्य।

6. उत्तर C
   - कथन 1 गलत: भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान, औपनिवेशिक राज्य द्वारा ब्रिटेन में निवेश योग्य पूंजी का न केवल एकतरफा हस्तांतरण हुआ था, बल्कि असमान विनिमय दिन-ब-दिन भारत के वाणिज्य, व्यापार और संपन्न हथकरघा उद्योग को भी कमजोर कर रहा था।
   - पूरे औपनिवेशिक शासन के दौरान, राज्य की आर्थिक दृष्टि प्राथमिक उत्पादों के निर्यात के लिए भारत की क्षमता को बढ़ाना और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की खरीद/आयात को बढ़ाना और पूंजी की निकासी के साथ-साथ राजस्व आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राजस्व बढ़ाना था।
   - कथन 2 सही है: उपनिवेशवादियों द्वारा भारत के औद्योगीकरण की भी उपेक्षा की गई थी - बुनियादी ढांचे का निर्माण भारत के औद्योगीकरण के लिए नहीं बल्कि इसके कच्चे माल के दोहन के लिए किया गया था।
   - जो भारतीय पूंजीपति उभरे वे ब्रिटिश वाणिज्यिक पूंजी पर अत्यधिक निर्भर थे और उद्योग के कई क्षेत्रों में ब्रिटिश फर्मों का वर्चस्व था, जैसे, शिपिंग, बैंकिंग, बीमा, कोयला, वृक्षारोपण फसलें और जूट।
   - कथन 3 गलत: स्वतंत्रता-पूर्व की अवधि पूरी तरह से लगभग ठहराव की अवधि थी, जिसमें उत्पादन की संरचना या उत्पादकता के स्तर में लगभग कोई बदलाव नहीं दिखा।
   - 20वीं सदी की पहली छमाही के दौरान कुल वास्तविक उत्पादन 2 प्रतिशत प्रति वर्ष या उससे भी कम होने का अनुमान लगाया गया था।

7. Answer A
   - Statement 2 incorrect: The plan period for Second Plan was 1956–61. The strategy of growth laid emphasis on rapid industrialisation with a focus on heavy industries and capital goods.
   - The plan was developed by Professor Mahalanobis. Due to the assumption of a closed economy, shortages of food and capital were felt during this Plan.
   - Statement 3 incorrect: The Plan period for Third Plan was 1961–65. The Plan specifically incorporated the development of agriculture as one of the objectives of planning in India besides, for the first time, considering the aim of balanced, regional development.
   - Enough misfortunes awaited this plan—two wars, one with China in 1961–62 and the other with Pakistan in 1965–66 along the Gujarat border and a severe drought-led famine in 1965–66 had to be faced. Due to heavy drain and diversion of funds, this plan utterly failed to meet its targets.
   - The target growth rate was 5.6%, but the actual growth rate was 2.4%

8. Answer C
   - Statement 1 is incorrect: The GDP deflator, also called implicit price deflator, is a measure of inflation. It is calculated by dividing the value of goods and services an economy produces in a particular year at current prices (Nominal GDP) to that of prices that prevailed during the base year (Real GDP) and then multiplying by 100. This ratio helps show the extent to which the increase in gross domestic product has happened on account of higher prices rather than increase in output.
   - Statement 2 is incorrect: The deflator covers the entire range of goods and services produced in the economy — as against the limited commodity baskets for the wholesale or consumer price indices — it is seen as a more comprehensive measure of inflation.
   - Statement 3 is incorrect: The gross domestic product implicit price deflator, or GDP deflator, measures changes in the prices of goods and services produced in the economy, including those exported to other countries. Prices of imports are excluded.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

7. उत्तर A
   - कथन 2 ग़लत: दूसरी योजना की योजना अवधि 1956-61 थी। विकास की रणनीति में भारी उद्योगों और पूंजीगत वस्तुओं पर ध्यान देने के साथ तेजी से औद्योगीकरण पर जोर दिया गया।
   - यह योजना प्रोफेसर महालनोबिस द्वारा विकसित की गई थी। बंद अर्थव्यवस्था की धारणा के कारण इस योजना के दौरान भोजन और पूंजी की कमी महसूस की गई।
   - कथन 3 गलत: तीसरी योजना की योजना अवधि 1961-65 थी। योजना में पहली बार संतुलित, क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य पर विचार करने के अलावा, भारत में योजना के उद्देश्यों में से एक के रूप में कृषि के विकास को शामिल किया गया।
   - इस योजना के लिए पर्याप्त दुर्भाग्य इंतजार कर रहे थे - दो युद्ध, एक 1961-62 में चीन के साथ और दूसरा 1965-66 में गुजरात सीमा पर पाकिस्तान के साथ और 1965-66 में भीषण सूखे के कारण अकाल का सामना करना पड़ा। भारी निकासी और धन की हेराफेरी के कारण यह योजना अपने लक्ष्यों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही।
   - लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 2.4% थी

8. उत्तर C
   - कथन 1 गलत है: जीडीपी डिफ्लेटर, जिसे अंतर्निहित मूल्य डिफ्लेटर भी कहा जाता है, मुद्रास्फीति का एक माप है। इसकी गणना किसी विशेष वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मौजूदा कीमतों (नाममात्र जीडीपी) पर आधार वर्ष (वास्तविक जीडीपी) के दौरान प्रचलित कीमतों से विभाजित करके और फिर 100 से गुणा करके की जाती है। यह अनुपात दिखाने में मदद करता है सकल घरेलू उत्पाद में किस हद तक वृद्धि उत्पादन में वृद्धि के बजाय ऊंची कीमतों के कारण हुई है।
   - कथन 2 गलत है: डिफ्लेटर अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की पूरी श्रृंखला को कवर करता है - थोक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के लिए सीमित कमोडिटी बास्केट के विपरीत - इसे मुद्रास्फीति के अधिक व्यापक उपाय के रूप में देखा जाता है।
   - कथन 3 गलत है: सकल घरेलू उत्पाद अंतर्निहित मूल्य डिफ्लेटर, या जीडीपी डिफ्लेटर, अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को मापता है, जिसमें अन्य देशों को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं भी शामिल हैं। आयात की कीमतें शामिल नहीं हैं।

9. Answer A
   - Statement 3 is incorrect: The Consumer Price Index (CPI) is a measure that examines the weighted average of prices of a basket of consumer goods and services.It measures price changes from the perspective of a retail buyer. There are four types of CPI:CPI for Industrial Workers (IW), CPI for Agricultural Labourer (AL),CPI for Rural Labourer (RL) and CPI (Rural/Urban/Combined).

10. Answer A
    Seigniorage:
    - Seigniorage refers to the profit from money creation.Seigniorage is the profit that accrues to the central banks by in the following ways:
    - While issuing currency, the reserves/backup that the RBI keeps with itself, these reserves give RBI interest Income on the total amount of currency in circulation (minus cost of printing currency)
    - Interest accruing from bank balances with central banks arises from funds banks have to hold with the central banks to meet their reserve requirements (CRR), either as interest-free balances or at below market interest rates.
    - The inflation tax concept which is measured as the product of the inflation rate and the monetary base. (Because of inflation the currency note that the public is holding loses value which reduces the liability of RBI in real terms) Hence, statement II is correct.
    - Thus, it is a way for governments to generate revenue without levying conventional taxes. Hence, statement I is correct.
    - Therefore, statement II is the correct explanation of statement I.
    - Hence, option A is correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

9. उत्तर A
   कथन 3 गलत है: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) एक माप है जो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी की कीमतों के भारित औसत की जांच करता है। यह खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। सीपीआई के चार प्रकार हैं: औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई (आईडब्ल्यू), कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई (एएल), ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई (आरएल) और सीपीआई (ग्रामीण/शहरी/संयुक्त)।

10. उत्तर ए
    सिग्नियोरेज:
    - सिग्नियोरेज का तात्पर्य धन सृजन से होने वाले लाभ से है। सिग्नियोरेज वह लाभ है जो केंद्रीय बैंकों को निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त होता है:
    - मुद्रा जारी करते समय आरबीआई अपने पास जो रिज़र्व/बैकअप रखता है, ये रिज़र्व आरबीआई को प्रचलन में मुद्रा की कुल राशि पर ब्याज आय देता है (मुद्रा मुद्रण की लागत घटाकर)
    - केंद्रीय बैंकों के बैंक शेषों से अर्जित होने वाला ब्याज उन निधियों से उत्पन्न होता है जिन्हें बैंकों को अपनी आरक्षित आवश्यकताओं (सीआरआर) को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंकों के पास रखना होता है, या तो ब्याज मुक्त शेष के रूप में या बाजार की ब्याज दरों से नीचे।
    - मुद्रास्फीति कर अवधारणा जिसे मुद्रास्फीति दर और मौद्रिक आधार के उत्पाद के रूप में मापा जाता है। (मुद्रास्फीति के कारण जनता के पास मौजूद मुद्रा नोट का मूल्य कम हो जाता है जिससे वास्तविक रूप में आरबीआई की देनदारी कम हो जाती है) इसलिए, कथन II सही है।
    - इस प्रकार, यह सरकारों के लिए पारंपरिक कर लगाए बिना राजस्व उत्पन्न करने का एक तरीका है। इसलिए, कथन I सही है।
    - इसलिए, कथन II कथन I की सही व्याख्या है।
    - अतः, विकल्प A सही है।

11. Answer B
Explanation
- Since independence and till 1993, India used to fix its exchange rate with respect to dollar and other major currencies and depending on economic situation, whenever required it used to adjust or devalue and revalue the rupee. This is called the "Fixed and Adjustable" exchange rate system. Hence, statement 1 is not correct.
- Managed Float: Under this system, the Central bank sometimes intervenes in the market to buy and sell foreign currencies in case the domestic currency becomes very volatile. For example, the Indian Rupee is a managed float. Hence, statement 2 is correct.

IMF's Classification of Stabilised Arrangement:
- The International Monetary Fund (IMF) classifies an exchange rate regime as a stabilized arrangement when it determines that the exchange rate has not moved beyond a 2% band in 6 months and that this stability has resulted from market interventions rather than market conditions. Hence, statement 3 is correct.

12. Answer C
Repo Rate:
- Repo is short form of "Repurchase Agreement". It is the rate at which commercial banks borrow from RBI by mortgaging their dated Government Securities and Treasury Bills. Hence, statement 1 is not correct.
- Reverse Repo Rate: It is the rate at which RBI borrows from commercial banks by mortgaging its dated Government Securities and Treasury Bills. The (fixed) interest rate at which the Reserve Bank absorbs liquidity, on an overnight basis, from banks against the collateral of eligible government securities under the LAF. Hence, statement 2 is not correct.

Marginal Standing Facility (MSF):
- It is a loan facility given by RBI to banks which have current and SGL (Subsidiary General Ledger) accounts with RBI.
- It is a loan for overnight. The loan is given against the mortgage of eligible securities.
- Usually, the interest rate for MSF is Repo rate plus 1%
- Hence, statement 3 is not correct.

11. उत्तर B
स्पष्टीकरण

- आजादी के बाद से और 1993 तक, भारत डॉलर और अन्य प्रमुख मुद्राओं के संबंध में अपनी विनिमय दर तय करता था और आर्थिक स्थिति के आधार पर, जब भी आवश्यकता होती थी, रुपये को समायोजित या अवमूल्यन और पुनर्मूल्यांकन करता था। इसे "निश्चित एवं समायोज्य" विनिमय दर प्रणाली कहा जाता है। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।
- प्रबंधित फ्लोट: इस प्रणाली के तहत, केंद्रीय बैंक कभी-कभी घरेलू मुद्रा के बहुत अस्थिर होने की स्थिति में विदेशी मुद्रा खरीदने और बेचने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करता है। उदाहरण के लिए, भारतीय रुपया एक प्रबंधित फ्लोट है। अतः, कथन 2 सही है।

स्थिर व्यवस्था का आईएमएफ का वर्गीकरण:

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) विनिमय दर व्यवस्था को एक स्थिर व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत करता है जब यह निर्धारित होता है कि विनिमय दर 6 महीनों में 2% बैंड से आगे नहीं बढ़ी है और यह स्थिरता बाजार की स्थितियों के बजाय बाजार के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप हुई है। अतः, कथन 3 सही है।

12. उत्तर C
रेपो दर:

- रेपो "पुनर्खरीद समझौता" का संक्षिप्त रूप है। यह वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों को गिरवी रखकर आरबीआई से उधार लेते हैं। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।
- रिवर्स रेपो दर: यह वह दर है जिस पर आरबीआई अपनी दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों को गिरवी रखकर वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है। (निश्चित) ब्याज दर जिस पर रिज़र्व बैंक एलएएफ के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों की संपार्श्विक के विरुद्ध बैंकों से रात भर के आधार पर तरलता को अवशोषित करता है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ):

- यह आरबीआई द्वारा उन बैंकों को दी गई एक ऋण सुविधा है जिनके आरबीआई के साथ चालू और एसजीएल (सब्सिडियरी जनरल लेजर) खाते हैं।
- यह रात भर के लिए ऋण है. ऋण पात्र प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर दिया जाता है।
- आमतौर पर, एमएसएफ के लिए ब्याज दर रेपो दर प्लस 1% है
- इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।

13. Answer B
- The RBI (Reserve Bank of India) in 2016 approved AA as a new class of NBFC (Non Banking Financial Companies), whose primary responsibility is to facilitate the transfer of user's financial data with their explicit consent. Hence, statement 1 is not correct.
- AAs enable flow of data between Financial Information Providers (FIPs) and Financial Information Users (FIUs). Hence, statement 2 is correct.
- The architecture of AA is based on the Data Empowerment and Protection Architecture (DEPA) framework. Hence, statement 3 is correct.

14. Answer A
- Labour Force Participation Rate (LFPR): LFPR is defined as the percentage of persons in the labour force (i.e. working or seeking or available for work) in the population. Hence, statement 1 is not correct.
- Worker Population Ratio (WPR): WPR is defined as the percentage of employed persons in the population. Hence, statement 2 is not correct.
- Unemployment Rate (UR): UR is defined as the percentage of persons unemployed among the persons in the labour force. Hence, statement 3 is correct.

15. Answer D
- Payments banks were part of the Reserve Bank of India's strategy of offering differentiated banking licenses.
- A committee headed by Dr. Nachiket Mor recommended setting up a 'Payments Bank' to cater to the lower income groups and small businesses. Hence, statement 1 is not correct.
  - A payments bank is a differentiated bank, offering a limited range of products.
- It can accept demand deposits only that is savings and current accounts, not time deposits. Hence, statement 2 is not correct.
- Payment banks are restricted to holding a maximum balance of Rs.2,00,000 (Rupees Two lakh only) per individual customer.
  - Payment Banks cannot accept Non-Resident Indian (NRI) deposits. Hence, statement 3 is not correct.

13. उत्तर B
- आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) ने 2016 में एए को एनबीएफसी (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) की एक नई श्रेणी के रूप में मंजूरी दे दी, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी उपयोगकर्ता की स्पष्ट सहमति से उनके वित्तीय डेटा के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना है। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।
- एए वित्तीय सूचना प्रदाताओं (एफआईपी) और वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं (एफआईयू) के बीच डेटा के प्रवाह को सक्षम बनाता है। अतः, कथन 2 सही है।
- AA का आर्किटेक्चर डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर (DEPA) फ्रेमवर्क पर आधारित है। अतः, कथन 3 सही है।

14. उत्तर A
- श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर): एलएफपीआर को जनसंख्या में श्रम बल (यानी काम करने वाले या काम की तलाश करने वाले या उपलब्ध) व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।
- श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर): डब्ल्यूपीआर को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।
- बेरोजगारी दर (यूआर): यूआर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। अतः, कथन 3 सही है।

15. उत्तर डी
- भुगतान बैंक विभेदित बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करने की भारतीय रिज़र्व बैंक की रणनीति का हिस्सा थे।
- डॉ. नचिकेत मोर की अध्यक्षता वाली एक समिति ने निम्न आय वर्ग और छोटे व्यवसायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 'पेमेंट्स बैंक' स्थापित करने की सिफारिश की। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।
  - भुगतान बैंक एक विभेदित बैंक है, जो उत्पादों की सीमित श्रृंखला पेश करता है।
- यह केवल बचत और चालू खातों में मांग जमा स्वीकार कर सकता है, सावधि जमा नहीं। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।
- भुगतान बैंक प्रति व्यक्तिगत ग्राहक रु. 2,00,000 (केवल दो लाख रुपये) की अधिकतम शेष राशि रखने तक सीमित हैं।
  - भुगतान बैंक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमा स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।

16. Answer A
- It is an institution established on a cooperative basis to deal with the ordinary banking business. Cooperative banks are founded by collecting funds through shares, accepting deposits, and granting loans. Hence, statement 1 is correct.
- The Reserve Bank of India (RBI) has revised the Supervisory Action Framework (SAF) for Urban Co-operative Banks (UCBs). It seeks to ensure expeditious resolution of financial stress faced by some of the UCBs. Hence, statement 2 is not correct.
- They are Cooperative credit societies where members from a community group together to extend loans to each other, at favorable terms.
- They are registered under the Cooperative Societies Act of the State concerned or the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002. Hence, statement 3 is not correct.

17. Answer B
Explanation
The above statement describes the capitalist economy. In a market economy, also called capitalism, only those consumer goods will be produced that are in demand, i.e., goods that can be sold profitably either in the domestic or in the foreign markets. In a capitalist society the goods produced are distributed among people not on the basis of what people need but on the basis of what people can afford and are willing to purchase.

18. Answer C
Explanation
- The evergreening of patents is a practice of tweaking drugs in order to extend their patent term and thus their profitability. Hence, statement 1 is correct.
- The Indian Patents Act 1970 introduced many provisions to prevent the mischievous practice of "evergreening" of patents. Hence, statement 2 is not correct.
- This is to aid millions of people who can't afford the expensive modified drugs, as well as the development of the domestic generic drug market. Hence, statement 3 is not correct.

16. उत्तर ए
- यह सामान्य बैंकिंग व्यवसाय से निपटने के लिए सहकारी आधार पर स्थापित एक संस्था है। सहकारी बैंकों की स्थापना शेयरों के माध्यम से धन एकत्र करके, जमा स्वीकार करके और ऋण देकर की जाती है। अतः, कथन 1 सही है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शहरी सहकारी बैंकों (UCB) के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (SAF) को संशोधित किया है। इसका उद्देश्य कुछ यूसीबी द्वारा सामना किए जा रहे वित्तीय तनाव का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।
- वे सहकारी ऋण समितियां हैं जहां एक समुदाय के सदस्य एक-दूसरे को अनुकूल शर्तों पर ऋण देने के लिए मिलकर काम करते हैं।
- वे संबंधित राज्य के सहकारी सोसायटी अधिनियम या बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत हैं। इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।

17. उत्तर B
स्पष्टीकरण
- उपरोक्त कथन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वर्णन करता है। बाज़ार अर्थव्यवस्था में, जिसे पूंजीवाद भी कहा जाता है, केवल उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा जिनकी मांग है, यानी वे वस्तुएं जिन्हें घरेलू या विदेशी बाज़ारों में लाभप्रद रूप से बेचा जा सकता है। पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच इस आधार पर नहीं वितरित किया जाता है कि लोगों को क्या चाहिए, बल्कि इस आधार पर वितरित किया जाता है कि लोग क्या खरीद सकते हैं और क्या खरीदने के इच्छुक हैं।

18. उत्तर C
स्पष्टीकरण
- पेटेंटों को सदाबहार बनाना उनकी पेटेंट अवधि और इस प्रकार उनकी लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए दवाओं में बदलाव करने की एक प्रथा है। अतः, कथन 1 सही है।
- भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 ने पेटेंट के "सदाबहार" होने की शरारती प्रथा को रोकने के लिए कई प्रावधान पेश किए। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।
- इसका उद्देश्य उन लाखों लोगों की सहायता करना है जो महंगी संशोधित दवाएं नहीं खरीद सकते, साथ ही घरेलू जेनेरिक दवा बाजार का विकास भी करना है। इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

19. Answer B
- IMF Bailouts: Countries seek help from the IMF usually when their economies face a major macroeconomic risk, mostly currency crisis (such as the ones Sri Lanka is facing). Hence, statement 1 is correct.
- Countries seek such assistance from the IMF to meet their external debt and other obligations, to purchase essential imports, and to prop up the exchange value of their currencies.
- The IMF lends money to the troubled economies often in the form of Special Drawing Rights (SDRs). Hence, statement 2 is not correct.
- SDRs simply represent a basket of five currencies, namely the U.S. dollar, the euro, the Chinese yuan, the Japanese yen, and the British pound.
- This lending is carried out by a number of lending programs such as extended credit facility, flexible credit lines, stand-by agreements, etc. Hence, statement 3 is correct.

20. Answer C

Full-Reserve Banking: Safeguarding Deposits

- Under full-reserve banking, banks are strictly prohibited from lending out demand deposits received from customers reducing the risk of bank runs. Hence, statement 1 is correct.
- Instead, they must always hold 100% of these deposits in their vaults, acting merely as custodians.

Fractional-Reserve Banking: Expanding Credit and Risk

- Fractional-reserve banking system, currently in practice, allows banks to lend more money than the cash they hold in their vaults. Hence, statement 2 is correct.
- This system relies heavily on electronic money for lending.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

19. उत्तर B
- आईएमएफ बेलआउट: देश आमतौर पर आईएमएफ से मदद मांगते हैं जब उनकी अर्थव्यवस्थाएं बड़े व्यापक आर्थिक जोखिम का सामना करती हैं, ज्यादातर मुद्रा संकट (जैसे कि श्रीलंका का सामना करना पड़ रहा है)। अतः, कथन 1 सही है।
- देश अपने विदेशी ऋण और अन्य दायित्वों को पूरा करने, आवश्यक आयात खरीदने और अपनी मुद्राओं के विनिमय मूल्य को बढ़ाने के लिए आईएमएफ से ऐसी सहायता चाहते हैं।
- आईएमएफ अक्सर विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) के रूप में संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं को पैसा उधार देता है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।
- एसडीआर केवल पांच मुद्राओं की एक टोकरी का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात् अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड।
- यह उधार कई उधार कार्यक्रमों जैसे विस्तारित क्रेडिट सुविधा, लचीली क्रेडिट लाइनें, स्टैंड-बाय समझौते आदि द्वारा किया जाता है। इसलिए, कथन 3 सही है।

20. उत्तर C

पूर्ण-रिज़र्व बैंकिंग: जमा की सुरक्षा

- पूर्ण-रिज़र्व बैंकिंग के तहत, बैंकों को ग्राहकों से प्राप्त मांग जमा को उधार देने से सख्ती से प्रतिबंधित किया जाता है, जिससे बैंक चलाने का जोखिम कम हो जाता है। अतः, कथन 1 सही है।
- इसके बजाय, उन्हें केवल संरक्षक के रूप में कार्य करते हुए, इन जमाओं का 100% हमेशा अपनी तिजोरियों में रखना चाहिए।

फ्रैक्शनल-रिज़र्व बैंकिंग: क्रेडिट और जोखिम का विस्तार

- आंशिक-आरक्षित बैंकिंग प्रणाली, जो वर्तमान में चलन में है, बैंकों को उनकी तिजोरी में रखी नकदी से अधिक धन उधार देने की अनुमति देती है। अतः, कथन 2 सही है।
- यह प्रणाली उधार देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक धन पर बहुत अधिक निर्भर करती है।

21. Answer C

Cash Reserve Ratio (CRR):

- The amount of cash that the scheduled commercial banks are required to maintain with RBI with respect to their NDTL (on a fortnightly basis) is called CRR. Hence, statement 1 is not correct.

Statutory Liquidity Ratio (SLR):

- The amount of reserves that the scheduled commercial banks are required to maintain with themselves on a daily basis in safe and liquid assets such as government securities, gold and cash with respect to their NDTL is called SLR. Hence, statement 2 is not correct.
- Banking Regulation Act 1949 (Section 24) governs maintenance of SLR for all banks (scheduled and non-scheduled) commercial and cooperative. Hence, statement 3 is not correct.

22. Answer B

- RBI provides "Ways and Means Advances" (WMA) – as a temporary loan facility to the centre and state/UT governments as a banker to the government. Hence, statement 1 is not correct.
- The WMA scheme is designed to meet temporary mismatches in the receipts and payments of the government. This facility can be availed by the government if it needs immediate cash from the RBI. The WMA is a loan facility from the RBI for 90 days which implies that the government has to vacate the facility after 90 days.
- The interest rate for WMA is currently charged at the repo rate. Hence, statement 2 is correct.
- The limits for WMA are mutually decided by the RBI and the Government of India. WMA is just a loan paper and is non-tradable (T-bills, Dated Securities, SDL and Cash Management Bills are tradable). WMAs are not used to fund Fiscal deficit. Hence, statement 3 is correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

21. उत्तर C

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर):

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने एनडीटीएल (पाक्षिक आधार पर) के संबंध में आरबीआई के पास जो नकदी बनाए रखने की आवश्यकता होती है, उसे सीआरआर कहा जाता है। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।

वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर):

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने एनडीटीएल के संबंध में सरकारी प्रतिभूतियों, सोने और नकदी जैसी सुरक्षित और तरल संपत्तियों में दैनिक आधार पर अपने पास आरक्षित राशि बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसे एसएलआर कहा जाता है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (धारा 24) सभी बैंकों (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित) वाणिज्यिक और सहकारी के लिए एसएलआर के रखरखाव को नियंत्रित करता है। इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।

22. उत्तर B

- RBI सरकार के बैंकर के रूप में केंद्र और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को अस्थायी ऋण सुविधा के रूप में "वेज़ एंड मीन्स एडवांस" (WMA) प्रदान करता है। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।
- WMA योजना सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों में अस्थायी विसंगतियों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई है। अगर सरकार को आरबीआई से तत्काल नकदी की जरूरत है तो इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। WMA आरबीआई से 90 दिनों के लिए एक ऋण सुविधा है जिसका अर्थ है कि सरकार को 90 दिनों के बाद यह सुविधा खाली करनी होगी।
- WMA के लिए ब्याज दर वर्तमान में रेपो दर पर ली जाती है। अतः, कथन 2 सही है।
- WMA की सीमाएँ RBI और भारत सरकार द्वारा पारस्परिक रूप से तय की जाती हैं। डब्लूएमए सिर्फ एक ऋण पत्र है और गैर-व्यापार योग्य है (टी-बिल, दिनांकित प्रतिभूतियां, एसडीएल और नकद प्रबंधन बिल व्यापार योग्य हैं)। WMA का उपयोग राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के लिए नहीं किया जाता है। अतः, कथन 3 सही है।

23. Answer A

Priority Sector Lending:

- The description of the priority sectors was first formalised in 1972 on the basis of the report submitted by the Informal Study Group on Statistics relating to advances to the Priority Sectors constituted by the Reserve Bank in May 1971.
- First time in 1974, the banks were given a target of 33.3% as a share of the priority sector in the total bank credit.
- Priority sectors refer to those sectors of the economy which may not get timely and adequate credit in the absence of this special scheme.
- Typically, these are small value loans to those sectors of the society/economy that impact large segments of the population and weaker sections, and to the sectors which are employment intensive such as agriculture and small enterprises. Hence, statement 1 is correct.
- Commercial banks have to lend at least 40 percent of their loan to PSL category while S Small finance banks (SFB) are required to extend 75 percent of its Adjusted Net Bank Credit (ANBC) to the sectors eligible for classification as PSL by the Reserve Bank. Failure to meet this lending will attract penal charges. Hence, statement 2 is not correct.
- Scheduled Commercial Banks (SCBs) having any shortfall in lending to priority sectors are allocated amounts for contribution to the Rural Infrastructure Development Fund (RIDF). Hence, statement 3 is not correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

23. उत्तर A

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण:

- प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के विवरण को पहली बार मई 1971 में रिज़र्व बैंक द्वारा गठित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अग्रिमों से संबंधित सांख्यिकी पर अनौपचारिक अध्ययन समूह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर 1972 में औपचारिक रूप दिया गया था।
- 1974 में पहली बार बैंकों को कुल बैंक ऋण में प्राथमिकता क्षेत्र की हिस्सेदारी के रूप में 33.3% का लक्ष्य दिया गया था।
- प्राथमिकता क्षेत्र से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों से है जिन्हें इस विशेष योजना के अभाव में समय पर और पर्याप्त ऋण नहीं मिल पाता है।
- आमतौर पर, ये समाज/अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों के लिए छोटे मूल्य के ऋण होते हैं जो आबादी के बड़े हिस्से और कमजोर वर्गों को प्रभावित करते हैं, और उन क्षेत्रों के लिए जो रोजगार गहन हैं जैसे कि कृषि और छोटे उद्यम। अतः, कथन 1 सही है।
- वाणिज्यिक बैंकों को अपने ऋण का कम से कम 40 प्रतिशत पीएसएल श्रेणी को उधार देना होता है, जबकि एस लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को अपने समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) का 75 प्रतिशत रिजर्व बैंक द्वारा पीएसएल के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र क्षेत्रों को देना होता है। . इस उधार को पूरा करने में विफलता पर दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।
- जिन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने में कोई कमी है, उन्हें ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि (आरआईडीएफ) में योगदान के लिए राशि आवंटित की जाती है। इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।

24. Answer D

- Statement 1 is incorrect: Nominal Effective Exchange Rate (NEER) is obtained by calculating the geometric average of the exchange rate of rupee in relation to different foreign currencies depending upon their trade volumes with India. Real Effective Exchange Rate (REER) is inflation adjusted exchange rate (CPI in case of India). Hence, both REER and NEER measures the position of a currency not just with respect to dollars but also with respect to other foreign currencies.
- Statement 2 is incorrect: REER is adjusted with the data of the Consumer Price Index level to measure the status of the Indian currency with respect to the entire global market and not with respect to dollars only.
- Statement 3 is incorrect: Greater the value of REER for India, indicates appreciation in the Indian currency with respect to the other currencies, this would make the exports of India less attractive to the foreign buyers, as it would cost them more rupees to purchase the same commodity.

25. Answer B

- Option B is the Correct answer The Repo Rate is the (fixed) interest rate at which the RBI provides overnight liquidity up to a certain limit (0.25% of their NDTL) to banks against the collateral of government and other approved securities under the Liquidity Adjustment Facility (LAF). Repo is short form of "Repurchase Agreement".
- Marginal Standing Facility (MSF) is a facility introduced in 2011, under which scheduled commercial banks can borrow additional amount of overnight money (over and above what is available to them through repo rate) from the Reserve Bank by dipping into their SLR portfolio up to a limit at a penal rate of interest. This provides a safety valve against unanticipated liquidity shocks to the banking system.

24. उत्तर D

- कथन 1 गलत है: नाममात्र प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) भारत के साथ उनके व्यापार की मात्रा के आधार पर विभिन्न विदेशी मुद्राओं के संबंध में रुपये की विनिमय दर के ज्यामितीय औसत की गणना करके प्राप्त की जाती है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) मुद्रास्फीति समायोजित विनिमय दर (भारत के मामले में सीपीआई) है। इसलिए, आरईईआर और एनईईआर दोनों न केवल डॉलर के संबंध में बल्कि अन्य विदेशी मुद्राओं के संबंध में भी मुद्रा की स्थिति को मापते हैं।
- कथन 2 गलत है: आरईईआर को केवल डॉलर के संबंध में नहीं, बल्कि पूरे वैश्विक बाजार के संबंध में भारतीय मुद्रा की स्थिति को मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक स्तर के डेटा के साथ समायोजित किया जाता है।
- कथन 3 गलत है: भारत के लिए आरईईआर का अधिक मूल्य, अन्य मुद्राओं के संबंध में भारतीय मुद्रा में सराहना को इंगित करता है, इससे विदेशी खरीदारों के लिए भारत का निर्यात कम आकर्षक हो जाएगा, क्योंकि इससे उन्हें खरीदने के लिए अधिक रुपये खर्च होंगे।

25. उत्तर B

- विकल्प बी सही उत्तर है रेपो दर वह (निश्चित) ब्याज दर है जिस पर आरबीआई तरलता समायोजन के तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ बैंकों को एक निश्चित सीमा (उनके एनडीटीएल का 0.25%) तक रात भर की तरलता प्रदान करता है। सुविधा (एलएएफ)। रेपो "पुनर्खरीद समझौता" का संक्षिप्त रूप है।
- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) 2011 में शुरू की गई एक सुविधा है, जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने एसएलआर पोर्टफोलियो में डुबकी लगाकर रिजर्व बैंक से रातोंरात अतिरिक्त धनराशि (रेपो दर के माध्यम से उनके लिए उपलब्ध राशि से अधिक) उधार ले सकते हैं। ब्याज की दंडात्मक दर पर एक सीमा। यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित तरलता झटके के खिलाफ एक सुरक्षा वाल्व प्रदान करता है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

26. Answer B
- Statement 1 is Incorrect: The amount of cash that the scheduled and non-scheduled commercial banks are required to maintain with RBI with respect to their Net Deposit and Time Liabilities (on a fortnightly basis) is called the Cash Reserve Ratio (CRR).
- Statement 2 is Incorrect: All Commercial and Cooperative Banks (either scheduled or non-scheduled) are required to maintain CRR and SLR. For scheduled banks, the maintenance of CRR is governed through The Reserve Bank of India Act 1934 and for Non-Scheduled banks CRR is governed through Banking Regulation Act 1949.
- The Banking Regulation Act 1949 (Section 24) governs maintenance of SLR for all banks (scheduled and non-scheduled) commercial and cooperative.
- Statement 3 is Correct: As per the RBI Act, 1934- "In terms of Section 42(1) of the RBI Act, 1934 the Reserve Bank, having regard to the needs of securing the monetary stability in the country, prescribes the CRR for SCBs without any floor or ceiling rate".

27. Answer A
- Statement 1 is incorrect: Scrip Share: A share given to the existing shareholders without any charge—also known as bonus share.
- Statement 2 is correct: Sweat Share :A share given to the employees of the company without any charge.
- Statement 3 is correct Futures :A trading allowed in shares where a future price is quoted for the shares and the payment and delivery takes place on the predetermined dates

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

26. उत्तर B
- कथन 1 गलत है: अनुसूचित और गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी शुद्ध जमा और सावधि देनदारियों (पाक्षिक आधार पर) के संबंध में आरबीआई के पास नकदी की वह मात्रा बनाए रखनी होती है, जिसे नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) कहा जाता है।
- कथन 2 गलत है: सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों (या तो अनुसूचित या गैर-अनुसूचित) को सीआरआर और एसएलआर बनाए रखना आवश्यक है। अनुसूचित बैंकों के लिए, सीआरआर का रखरखाव भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है और गैर-अनुसूचित बैंकों के लिए सीआरआर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है।
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (धारा 24) सभी बैंकों (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित) वाणिज्यिक और सहकारी के लिए एसएलआर के रखरखाव को नियंत्रित करता है।
- कथन 3 सही है: आरबीआई अधिनियम, 1934 के अनुसार- "आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के संदर्भ में, रिजर्व बैंक, देश में मौद्रिक स्थिरता को सुरक्षित रखने की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सीआरआर निर्धारित करता है बिना किसी न्यूनतम या अधिकतम दर वाले एससीबी"।

27. उत्तर A
- कथन 1 गलत है: स्क्रिप शेयर: मौजूदा शेयरधारकों को बिना किसी शुल्क के दिया गया शेयर - जिसे बोनस शेयर भी कहा जाता है।
- कथन 2 सही है: स्वेट शेयर: कंपनी के कर्मचारियों को बिना किसी शुल्क के दिया गया शेयर।
- कथन 3 सही है। वायदा: शेयरों में एक व्यापार की अनुमति है जहां शेयरों के लिए भविष्य की कीमत उद्धृत की जाती है और भुगतान और वितरण पूर्व निर्धारित तिथियों पर होता है।

28. Answer C
- Statement 1 is correct: A Participatory Note (PN or P-Note) in essence, is a derivative instrument issued in foreign jurisdictions, by a SEBI registered FII, against Indian securities—the Indian security instrument may be equity, debt, derivatives or may even be an index.
- Statement 2 is incorrect: The investor in PN does not own the underlying Indian security, which is held by the FII who issues the PN.
- Statement 3 is correct: The PN holder also does not enjoy any voting rights in relation to security/shares referenced by the PN.

29. Answer A

Disinflation:

- Disinflation refers to the trend when the inflation rate decelerates.
- It refers to a period when even though prices are rising, it is happening at a slower rate each passing month. Hence, statement 1 is not correct.

Deflation:

- Deflation is a general decline in prices for goods and services, typically associated with a contraction in the supply of money and credit in the economy. Imagine if the general prices level in June 2023 was 5% lower than what it was in June 2022. Hence, statement 2 is not correct.

Reflation:

- Reflation typically follows deflation as policymakers try to pump up economic activity either by government spending more and/or interest rates being reduced. Hence, statement 3 is correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

28. उत्तर सी
- कथन 1 सही है: एक पार्टिसिपेटरी नोट (पीएन या पी-नोट) संक्षेप में, भारतीय प्रतिभूतियों के खिलाफ सेबी पंजीकृत एफआईआई द्वारा विदेशी न्यायालयों में जारी एक व्युत्पन्न उपकरण है - भारतीय सुरक्षा उपकरण इक्विटी, ऋण, डेरिवेटिव या हो सकता है यहां तक कि एक सूचकांक भी हो।
- कथन 2 गलत है: पीएन में निवेशक के पास अंतर्निहित भारतीय सुरक्षा नहीं है, जो पीएन जारी करने वाले एफआईआई के पास है।
- कथन 3 सही है: पीएन धारक को पीएन द्वारा संदर्भित सुरक्षा/शेयरों के संबंध में किसी भी मतदान अधिकार का आनंद नहीं मिलता है।

29. उत्तर ए

अवस्फीति:

अवस्फीति उस प्रवृत्ति को संदर्भित करती है जब मुद्रास्फीति की दर कम हो जाती है।

यह उस अवधि को संदर्भित करता है जब कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन यह हर गुजरते महीने धीमी गति से हो रही है। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।

अपस्फीति:

अपस्फीति वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में एक सामान्य गिरावट है, जो आमतौर पर अर्थव्यवस्था में धन और ऋण की आपूर्ति में संकुचन से जुड़ी होती है। कल्पना करें कि जून 2023 में सामान्य मूल्य स्तर जून 2022 की तुलना में 5% कम था। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

रिफ़्लेशन:

रिफ्लेशन आम तौर पर अपस्फीति के बाद होता है क्योंकि नीति निर्माता या तो सरकारी खर्च अधिक करके और/या ब्याज दरों को कम करके आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अतः, कथन 3 सही है।

30. Answer C

Greedflation

- Greedflation refers to the situation where corporate greed drives inflation. Hence, statement 1 is correct.
- Rather than a wage-price spiral, it is a Profit-Price Spiral where companies exploit inflation by raising prices excessively, going beyond covering their increased costs, and aiming to maximize their profit margins. These further fuels inflation. Hence, statement 2 is correct.

Impact:

- Greedflation disproportionately impacts low-income and middle-class individuals, reducing their consumption and lowering their standards of living. Hence, statement 3 is correct.

31. Answer D

- Inflation, as defined by the International Monetary Fund, is the rate of increase in prices over a given period, encompassing a broad measure of overall price increases or for specific goods and services.
- Cost-push inflation is driven by an increase in the production costs for goods and services. This can be caused by factors such as increased incomes, increased costs of raw materials, or disruptions in the supply chain. Hence, statement 1 is not correct.
- Demand Pull inflation occurs when the demand for goods and services exceeds their supply. When the overall demand in the economy is high, consumers are willing to pay more for the available goods and services, leading to a general rise in prices. Hence, statement 2 is not correct.
- Headline inflation is a measure of the total inflation within an economy, including commodities such as food and energy prices, which tend to be much more volatile and prone to inflationary spikes.
    - The headline inflation figure is reported through the Consumer Price Index (CPI), which calculates the cost to purchase a fixed basket of goods to determine how much inflation is occurring in the broad economy. Hence, statement 3 is not correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

30. उत्तर सी

ग्रीडफ्लेशन

- ग्रीडफ्लेशन मुद्रास्फीति उस स्थिति को संदर्भित करती है जहां कॉर्पोरेट ग्रीडफ्लेशन को बढ़ाता है। अतः, कथन 1 सही है।
- वेतन-मूल्य सर्पिल के बजाय, यह एक लाभ-मूल्य सर्पिल है जहां कंपनियां कीमतों में अत्यधिक वृद्धि करके, अपनी बढ़ी हुई लागत को कवर करने से परे जाकर और अपने लाभ मार्जिन को अधिकतम करने का लक्ष्य रखकर मुद्रास्फीति का फायदा उठाती हैं। ये मुद्रास्फीति को और बढ़ावा देते हैं। अतः, कथन 2 सही है।

प्रभाव:

- ग्रीडफ्लेशन कम आय और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों पर असमान रूप से प्रभाव डालती है, उनकी खपत को कम करती है और उनके जीवन स्तर को कम करती है। अतः, कथन 3 सही है।

31. उत्तर D

- मुद्रास्फीति, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा परिभाषित है, एक निश्चित अवधि में कीमतों में वृद्धि की दर है, जिसमें समग्र मूल्य वृद्धि या विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं की व्यापक माप शामिल है।
- लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन लागत में वृद्धि से प्रेरित होती है। यह बढ़ी हुई आय, कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसे कारकों के कारण हो सकता है। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।
- डिमांड पुल मुद्रास्फीति तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग उनकी आपूर्ति से अधिक हो जाती है। जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग अधिक होती है, तो उपभोक्ता उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार होते हैं, जिससे कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।
- हेडलाइन मुद्रास्फीति एक अर्थव्यवस्था के भीतर कुल मुद्रास्फीति का एक माप है, जिसमें खाद्य और ऊर्जा की कीमतें जैसी वस्तुएं शामिल हैं, जो बहुत अधिक अस्थिर होती हैं और मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना होती है।
    - हेडलाइन मुद्रास्फीति का आंकड़ा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है, जो यह निर्धारित करने के लिए कि व्यापक अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रास्फीति हो रही है, वस्तुओं की एक निश्चित टोकरी खरीदने की लागत की गणना करता है। इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।

32. Answer D
- Free Trade Agreements (FTA): A free trade agreement is a preferential arrangement in which members reduce tariffs on trade among themselves while maintaining their own tariff rates for trade with non-members. Hence, statement 1 is correct.
- Customs Union (CU): A customs union is a free trade agreement (FTA) in which members apply a common external tariff (CET) schedule to imports from non-members. Hence, statement 2 is correct.
    - Economic Union (EU): An economic union is a common market (CM) where member countries coordinate macroeconomic and exchange rate policies.
- Common Market (CM): A common market is a customs union (CU) where the movement of factors of production is relatively free amongst member countries. Hence, statement 3 is correct.

33. Answer A
- Deficit means shortage. Here, deficit refers to the shortage of money for expenditure.
- The gap between receipts and expenditure is called deficit.
- There are various types of deficits which are explained below:
    - Budget Deficit : It is the difference between Total Expenditure and Total Receipts. Budget Deficit is always Zero.
    - Budget Deficit = Total Expenditure- Total Receipts. Hence, pair 1 is not correctly matched.
    - Fiscal Deficit : It is the difference between Total Expenditure and Total Receipts except Borrowings and other liabilities.
    - Fiscal Deficit = Total Expenditure- Total Receipts except the Borrowing and other liabilities. Hence, pair 2 is not correctly matched.
    - Primary Deficit : It is measured by subtracting the interest payment from Fiscal Deficit.
    - Primary Deficit = Fiscal Deficit- Interest Payment. Hence, pair 3 is correctly matched.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

32. उत्तर D
- मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए): एक मुक्त व्यापार समझौता एक तरजीही व्यवस्था है जिसमें सदस्य गैर-सदस्यों के साथ व्यापार के लिए अपनी स्वयं की टैरिफ दरें बनाए रखते हुए आपस में व्यापार पर टैरिफ कम करते हैं। अतः, कथन 1 सही है।
- सीमा शुल्क संघ (सीयू): एक सीमा शुल्क संघ एक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है जिसमें सदस्य गैर-सदस्यों से आयात के लिए एक सामान्य बाहरी टैरिफ (सीईटी) अनुसूची लागू करते हैं। अतः, कथन 2 सही है।
    - आर्थिक संघ (ईयू): एक आर्थिक संघ एक सामान्य बाजार (सीएम) है जहां सदस्य देश व्यापक आर्थिक और विनिमय दर नीतियों का समन्वय करते हैं।
    - सामान्य बाजार (सीएम): एक सामान्य बाजार एक सीमा शुल्क संघ (सीयू) है जहां सदस्य देशों के बीच उत्पादन के कारकों की आवाजाही अपेक्षाकृत मुक्त होती है। अतः, कथन 3 सही है।

33. उत्तर A
- घाटे का अर्थ है कमी। यहाँ घाटे का तात्पर्य व्यय के लिए धन की कमी से है।
- प्राप्तियों और व्यय के बीच के अंतर को घाटा कहा जाता है।
- घाटे विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:
    - बजट घाटा: यह कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। बजट घाटा सदैव शून्य होता है।
    - बजट घाटा = कुल व्यय- कुल प्राप्तियाँ। इसलिए, जोड़ी 1 सही ढंग से सुमेलित नहीं है।
    - राजकोषीय घाटा: यह उधार और अन्य देनदारियों को छोड़कर कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है।
    - राजकोषीय घाटा = कुल व्यय- उधार और अन्य देनदारियों को छोड़कर कुल प्राप्तियाँ। इसलिए, जोड़ी 2 सही ढंग से सुमेलित नहीं है।
    - प्राथमिक घाटा: इसे राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान घटाकर मापा जाता है।
    - प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा- ब्याज भुगतान। अतः, जोड़ी 3 सही सुमेलित है।

34. Answer D
- During the boom phase, countercyclical fiscal policy tries to reduce the aggregate demand by reducing government expenditure and increasing tax levels. During the recession phase, countercyclical fiscal policy raises aggregate demand by increasing expenditure and reducing the tax levels. Hence, statement 2 is not correct.

Pro-cyclical Fiscal Policy Stance :
- Pro-cyclical is the opposite of countercyclical. Here, fiscal policy goes in line with the current mood of the business cycle i.e. amplifying them. For example, during the time of boom, the government makes high expenditures and doesn't hike taxes. Hence, statement 1 is not correct.

35. Answer D
Lorenz Curve: A Lorenz curve is a graphical representation of income inequality or wealth inequality developed by American economist Max Lorenz in 1905. The graph plots percentiles of the population on the horizontal axis according to income or wealth. Hence, option D is correct.

36. Answer B
- Major Land Reforms Introduced in India After Independence: A committee, under the Chairmanship of J. C. Kumarappan was appointed to look into the problem of land. The Kumarappa Committee's report recommended comprehensive agrarian reform measures. Hence, statement 1 is not correct.
- The Land Reforms of the independent India had four components:
  - The Abolition of the Intermediaries: The main aim of the abolition of intermediaries was to bring the cultivator into a direct relationship with the government. The abolition of intermediaries made almost 2 crore tenants the owners of the land they cultivated. Hence, statement 2 is correct.
  - Tenancy Reforms: Tenancy reforms were introduced to regulate rent, provide security of tenure, and confer ownership to tenants.
  - Fixing Ceilings on Landholdings: The Land Ceiling Act defines the size of land that an individual/family can own. The main objective of the ceiling legislation was the redistribution of the surplus land to the landless so as to make land distribution more equitable. Hence, statement 3 is correct.

34. उत्तर D
- तेजी के चरण के दौरान, प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति सरकारी व्यय को कम करके और कर के स्तर को बढ़ाकर कुल मांग को कम करने की कोशिश करती है। मंदी के चरण के दौरान, प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति व्यय में वृद्धि और कर के स्तर को कम करके कुल मांग को बढ़ाती है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति रुख:

- प्रो-साइक्लिकल, काउंटरसाइक्लिकल के विपरीत है। यहां, राजकोषीय नीति व्यापार चक्र के वर्तमान मूड के अनुरूप चलती है यानी उन्हें बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, तेजी के समय में, सरकार अधिक व्यय करती है और करों में वृद्धि नहीं करती है। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।

35. उत्तर D
लोरेंज वक्र: लोरेंज वक्र 1905 में अमेरिकी अर्थशास्त्री मैक्स लोरेंज द्वारा विकसित आय असमानता या धन असमानता का एक चित्रमय प्रतिनिधित्व है। ग्राफ आय या धन के अनुसार क्षैतिज अक्ष पर जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाता है। अतः, विकल्प D सही है।

36. उत्तर B
स्वतंत्रता के बाद भारत में किए गए प्रमुख भूमि सुधार: भूमि की समस्या को देखने के लिए जे.सी. कुमारप्पन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। कुमारप्पा समिति की रिपोर्ट ने व्यापक कृषि सुधार उपायों की सिफारिश की। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।

स्वतंत्र भारत के भूमि सुधार के चार घटक थे:

बिचौलियों का उन्मूलन: बिचौलियों के उन्मूलन का मुख्य उद्देश्य कृषक को सरकार के साथ सीधे संबंध में लाना था। बिचौलियों के उन्मूलन ने लगभग 2 करोड़ किरायेदारों को उस भूमि का मालिक बना दिया जिस पर वे खेती करते थे। अतः, कथन 2 सही है।

किरायेदारी सुधार: किराए को विनियमित करने, कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करने और किरायेदारों को स्वामित्व प्रदान करने के लिए किरायेदारी सुधार पेश किए गए थे।

भूमि जोत पर अधिकतम सीमा तय करना: भूमि सीमा अधिनियम उस भूमि के आकार को परिभाषित करता है जिस पर एक व्यक्ति/परिवार का स्वामित्व हो सकता है। सीलिंग कानून का मुख्य उद्देश्य भूमिहीनों को अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण करना था ताकि भूमि वितरण को अधिक न्यायसंगत बनाया जा सके। अतः, कथन 3 सही है।

37. Answer A
- Agriculture Census in India is conducted quinquennially (at five-year intervals) by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Hence, statement 1 is not correct.
- The first agriculture census was done in 1970-71 and the last such census was 2015-16 (July – June), which was 10th in series. Hence, statement 2 is not correct.
- The main objectives of the Agriculture Census are:
  - To describe structure and characteristics of agriculture by providing statistical data on operational holdings, including land utilization, irrigation, irrigated and unirrigated area under different crops, use of agricultural machinery and implements, use of fertilizers, seeds, agricultural credit etc.
  - To provide benchmark data for formulating new agricultural development programmes and for evaluating their progress. Hence, statement 3 is correct.

38. Answer D
- The beginning of Green Revolution is attributed to Norman Borlaug, an American scientist interested in agriculture. In the 1940's he began conducting research in Mexico and developed new disease resistance high yielding varieties of wheat. Because of its success, green revolution technologies spread worldwide in 1950's and 1960's. Hence, statement 1 is not correct.
- The idea of the Green Revolution was to use technology to increase food output and the introduction of more western type of farming techniques.
  - M.S. Swaminathan is known as the "Father of Green Revolution in India". Hence, statement 2 is not correct.

37. उत्तर A

भारत में कृषि जनगणना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा हर पांच साल में (पांच साल के अंतराल पर) आयोजित की जाती है। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।

पहली कृषि जनगणना 1970-71 में की गई थी और आखिरी ऐसी जनगणना 2015-16 (जुलाई-जून) थी, जो श्रृंखला में 10वीं थी। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

कृषि जनगणना के मुख्य उद्देश्य हैं:

भूमि उपयोग, सिंचाई, विभिन्न फसलों के तहत सिंचित और असिंचित क्षेत्र, कृषि मशीनरी और उपकरणों का उपयोग, उर्वरकों, बीजों का उपयोग, कृषि ऋण आदि सहित परिचालन जोत पर सांख्यिकीय डेटा प्रदान करके कृषि की संरचना और विशेषताओं का वर्णन करना।

नए कृषि विकास कार्यक्रमों को तैयार करने और उनकी प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए बेंचमार्क डेटा प्रदान करना। अतः, कथन 3 सही है।

38. उत्तर D
- हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय कृषि में रुचि रखने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। 1940 के दशक में उन्होंने मेक्सिको में शोध करना शुरू किया और गेहूं की नई रोग प्रतिरोधी उच्च उपज वाली किस्में विकसित कीं। इसकी सफलता के कारण, हरित क्रांति प्रौद्योगिकियां 1950 और 1960 के दशक में दुनिया भर में फैल गईं। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।
- हरित क्रांति का विचार खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और अधिक पश्चिमी प्रकार की कृषि तकनीकों की शुरूआत करना था।
  - एमएस। स्वामीनाथन को "भारत में हरित क्रांति के जनक" के रूप में जाना जाता है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

39. Answer A

About Minimum Support Price (MSP):

- MSP is the guaranteed amount paid to farmers when the government buys their produce. MSP does not have any legal backing till now and farmers can't demand it as a legal right. It is just government policy and an administrative decision to purchase some food grains at MSP. Hence, statement 1 is not correct.
- MSP is based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), which considers various factors such as cost of production, demand and supply, market price trends, inter-crop price parity, etc. However, The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) chaired by the Prime Minister of India makes the final decision (approval) on the level of MSPs. Hence, statement 2 is not correct.
- However, The Swaminathan Commission recommended that the MSP should at least be 50% more than the weighted average cost of Production (CoP), which it refers to as the C2 cost. Hence, statement 3 is correct.

40. Answer C

- Non-tax revenue is the recurring income earned by the government from sources other than taxes.
- Out of the given options, three are non-tax revenue sources for the Indian government.
  - Dividends received from Public Sector Undertakings (PSUs)
  - Fees charged for passport renewal
  - Grants received from foreign governments
- Income tax collected from individuals is a tax revenue source.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

39. उत्तर A

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बारे में:

- एमएसपी वह गारंटीकृत राशि है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी उपज खरीदती है। एमएसपी को अब तक कोई कानूनी समर्थन नहीं है और किसान इसे कानूनी अधिकार के रूप में मांग नहीं सकते हैं। एमएसपी पर कुछ अनाज खरीदने की बात सिर्फ सरकारी नीति और प्रशासनिक निर्णय है। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।
- एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों पर आधारित है, जो उत्पादन लागत, मांग और आपूर्ति, बाजार मूल्य रुझान, अंतर-फसल मूल्य समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है। हालांकि, कैबिनेट समिति भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामले (सीसीईए) एमएसपी के स्तर पर अंतिम निर्णय (अनुमोदन) करते हैं। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।
- हालाँकि, स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी कि एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत (सीओपी) से कम से कम 50% अधिक होना चाहिए, जिसे वह सी2 लागत के रूप में संदर्भित करता है। अतः, कथन 3 सही है।

40. उत्तर C

गैर-कर राजस्व सरकार द्वारा करों के अलावा अन्य स्रोतों से अर्जित आवर्ती आय है।

दिए गए विकल्पों में से तीन भारत सरकार के लिए गैर-कर राजस्व स्रोत हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से प्राप्त लाभांश

पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए शुल्क लिया जाता है

विदेशी सरकारों से प्राप्त अनुदान

व्यक्तियों से एकत्र किया गया आयकर एक कर राजस्व स्रोत है।

41. Answer A
- Poverty estimation in India is now carried out by NITI Aayog's task force through the calculation of the poverty line based on the data captured by the National Sample Survey Office under the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI). Hence, statement 1 is correct.
- As per the Tendulkar report, if people are spending less than Rs.27 per day in rural areas and Rs.33 per day in urban areas, then they will be considered BPL and arrive at a cut-off of 21.9% of the population as BPL in 2011-12. Hence, statement 2 is not correct.
- Rangarajan committee raised these limits to Rs.32 per day in the rural areas and Rs.47, per day in the urban area, and worked out a poverty line of 29.5% in 2011-12.

42. Answer A
Explanation

Flipping: The process of transferring the entire ownership of an Indian company to an overseas entity, accompanied by a transfer of all Intellectual property and all data hitherto owned by the Indian company.

43. Answer A
- India adopted the strategy of Import Substitution Industrialization (ISI) in the fifties. The chief objective was to build a self-reliant economy. From the Second Five Year Plan, there was determined thrust towards substitution of basic and capital goods industries. Hence, statement 1 is correct.
- The Fourth Five Year Plan emphasised on reduction of concentration of incomes, wealth and economic power to achieve social equality and justice. Hence, statement 2 is correct.
- The Fifth Five Year Plan was aimed at the removal of poverty and achievement of self-reliance. The Eighth Plan focussed on financial sector reforms. Hence, statement 3 is not correct.

41. उत्तर A
भारत में गरीबी का आकलन अब नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है। अतः, कथन 1 सही है।

तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार, यदि लोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति दिन 27 रुपये और शहरी क्षेत्रों में प्रति दिन 33 रुपये से कम खर्च कर रहे हैं, तो उन्हें बीपीएल माना जाएगा और आबादी का 21.9% कट-ऑफ पर पहुंच जाएगा। 2011-12 में बी.पी.एल. इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

रंगराजन समिति ने इन सीमाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 32 रुपये और शहरी क्षेत्र में 47 रुपये प्रति दिन तक बढ़ा दिया और 2011-12 में 29.5% की गरीबी रेखा तैयार की।

42. उत्तर A
फ़्लिपिंग: एक भारतीय कंपनी के संपूर्ण स्वामित्व को एक विदेशी इकाई को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया, साथ ही भारतीय कंपनी के स्वामित्व वाली सभी बौद्धिक संपदा और सभी डेटा के हस्तांतरण के साथ।

43. उत्तर A
भारत ने पचास के दशक में आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण (आईएसआई) की रणनीति अपनाई। मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना से, बुनियादी और पूंजीगत सामान उद्योगों के प्रतिस्थापन की ओर निर्धारित जोर दिया गया। अतः, कथन 1 सही है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक समानता और न्याय प्राप्त करने के लिए आय, धन और आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को कम करने पर जोर दिया गया। अतः, कथन 2 सही है।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी दूर करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। आठवीं योजना वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर केंद्रित थी। इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

44. Answer C
- Technical progress and trade growth in the world economy, and population growth in a country do not necessarily imply the economic growth in the country
- Capital formation refers to the process of adding capital goods to the stock over time. Economic growth of a country depends upon availability of capital either in the form of physical capital or human capital. Hence, economic growth will surely occur if there is capital formation in a particular country.

45. Answer C
- A surety bond can be defined in its simplest form as a written agreement to guarantee compliance, payment, or performance of an act.It is a unique type of insurance because it involves a three-party agreement. Hence, statement 2 is correct.
- Surety bond is provided by the insurance company on behalf of the contractor to the entity that is awarding the project. It will help contractors to have financial closure of their projects without depending upon only bank guarantees.
- Hence, statement 1 is correct.

46. Answer A

T+1 Settlement Cycle:
- In January 2023, India adopted the T+1 settlement cycle, where T represents the trade date. Hence, statement 1 is correct.
- This means that trade-related settlements occur within one business day or 24 hours of the actual transaction. Hence, statement 2 is not correct.
- India became the second country, after China, to implement the T+1 settlement cycle in top-listed securities. Hence, statement 3 is not correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

44. उत्तर C
- विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति और व्यापार वृद्धि, और किसी देश में जनसंख्या वृद्धि आवश्यक रूप से उस देश में आर्थिक विकास का संकेत नहीं देती है
- पूंजी निर्माण से तात्पर्य समय के साथ स्टॉक में पूंजीगत सामान जोड़ने की प्रक्रिया से है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि भौतिक पूंजी या मानव पूंजी के रूप में पूंजी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसलिए, यदि किसी विशेष देश में पूंजी निर्माण होता है तो आर्थिक विकास निश्चित रूप से होगा।

45. उत्तर C
- एक ज़मानत बांड को उसके सरलतम रूप में किसी अधिनियम के अनुपालन, भुगतान या प्रदर्शन की गारंटी के लिए एक लिखित समझौते के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह एक अद्वितीय प्रकार का बीमा है क्योंकि इसमें तीन-पक्षीय समझौता शामिल है। अतः, कथन 2 सही है।
- बीमा कंपनी द्वारा ठेकेदार की ओर से परियोजना प्रदान करने वाली इकाई को ज़मानत बांड प्रदान किया जाता है। इससे ठेकेदारों को केवल बैंक गारंटी पर निर्भर हुए बिना अपनी परियोजनाओं को वित्तीय रूप से बंद करने में मदद मिलेगी।
- अतः, कथन 1 सही है।

46. उत्तर A

T+1 निपटान चक्र:
- जनवरी 2023 में, भारत ने T+1 निपटान चक्र अपनाया, जहाँ T व्यापार तिथि का प्रतिनिधित्व करता है। अतः, कथन 1 सही है।
- इसका मतलब यह है कि व्यापार-संबंधी निपटान वास्तविक लेनदेन के एक व्यावसायिक दिन या 24 घंटों के भीतर होता है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।
- शीर्ष-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में T+1 निपटान चक्र लागू करने वाला भारत चीन के बाद दूसरा देश बन गया। इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।

47. Answer C
- Evergreening loans, a form of zombie lending, is a practice of extending new or additional loans to a borrower who is unable to repay the existing loans, thereby concealing the true status of the non-performing assets (NPAs) or bad loans. Hence, statement 1 is correct.
- Evergreening loans can create a false impression of the asset quality and profitability of banks and delay the recognition and resolution of stressed assets. Hence, statement 2 is correct.
- It can also undermine the credit discipline and moral hazard among borrowers, and erode the trust and confidence of depositors, investors and regulators.

48. Answer C
- An SEZ is a territory within a country that is typically duty-free (Fiscal Concession) and has different business and commercial laws chiefly to encourage investment and create employment. Hence, statement 1 is correct.
- Asia's first EPZ (Export Processing Zones) was established in 1965 at Kandla, Gujarat. Hence, statement 2 is correct.
- The Baba Kalyani led committee was constituted by the Ministry of Commerce and Industry to study the existing SEZ policy of India and had submitted its recommendations in November 2018. Hence, statement 3 is correct.

49. Answer D

Global Gender Gap Index
- It is released by the World Economic Forum.
- It benchmarks countries on their progress towards gender parity in four Key dimensions with Submatrices.
  - Economic Participation and Opportunity
  - Educational Attainment
  - Health and Survival
  - Political Empowerment

47. उत्तर C
- एवरग्रीनिंग लोन, ज़ोंबी ऋण का एक रूप, एक ऐसे उधारकर्ता को नए या अतिरिक्त ऋण देने की प्रथा है जो मौजूदा ऋण चुकाने में असमर्थ है, जिससे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) या खराब ऋणों की वास्तविक स्थिति छिप जाती है। अतः, कथन 1 सही है।
- एवरग्रीनिंग लोन बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता के बारे में गलत धारणा बना सकते हैं और तनावग्रस्त संपत्तियों की पहचान और समाधान में देरी कर सकते हैं। अतः, कथन 2 सही है।
- यह उधारकर्ताओं के बीच क्रेडिट अनुशासन और नैतिक खतरे को भी कमजोर कर सकता है, और जमाकर्ताओं, निवेशकों और नियामकों के विश्वास को कमजोर कर सकता है।

48. उत्तर C
- एसईजेड किसी देश के भीतर एक क्षेत्र है जो आम तौर पर शुल्क-मुक्त (राजकोषीय रियायत) होता है और इसमें मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार पैदा करने के लिए अलग-अलग व्यवसाय और वाणिज्यिक कानून होते हैं। अतः, कथन 1 सही है।
- एशिया का पहला EPZ (निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र) 1965 में कांडला, गुजरात में स्थापित किया गया था। अतः, कथन 2 सही है।
- भारत की मौजूदा एसईजेड नीति का अध्ययन करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बाबा कल्याणी के नेतृत्व वाली समिति का गठन किया गया था और उसने नवंबर 2018 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। इसलिए, कथन 3 सही है।

49. उत्तर D

वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक
- इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है।
- यह सबमैट्रिसेस के साथ चार प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता की दिशा में देशों की प्रगति पर बेंचमार्क करता है।
  - आर्थिक भागीदारी और अवसर
  - शिक्षा प्राप्ति
  - स्वास्थ्य और जीवन रक्षा
  - राजनीतिक सशक्तिकरण

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

50. Answer A
- SEBI is a Statutory Body (a Non-Constitutional body which is set up by a Parliament) established on 12th April, 1992 in accordance with the provisions of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992. Hence, statement 1 is not correct.
- It performs the triple functions as a quasi-legislative, quasi-judicial and quasi-executive body. Hence, statement 2 is correct.
- By Securities Laws (Amendment) Act, 2014, SEBI is now able to regulate any money pooling scheme worth Rs.100 cr. or more and attach assets in case of non-compliance. Hence, statement 3 is correct.

51. Answer C
- It is a new Scheme after the merger of existing Schemes for Beggars and Transgenders. Hence, statement 1 is correct.
- Through Composite Medical Health it provides a comprehensive package in convergence with Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana (PM-JAY) supporting Gender-Reaffirmation surgeries through selected hospitals. Hence, statement 2 is correct.

52. Answer A
- It is a Central Sector Scheme with 100% funding from the Government of India. Hence, statement 1 is correct.
- Scope of the Scheme: The scheme was initially meant for Small and Marginal Farmers (SMFs) having landholding up to 2 hectares but the scope of the scheme was extended to cover all landholding farmers. Hence, statement 2 is not correct.
- Physical Verification Module: A mandatory physical verification of 5% beneficiaries every year is being done as per the provisions laid down in the scheme. Hence, statement 3 is not correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

50. उत्तर A
- सेबी एक वैधानिक निकाय (एक गैर-संवैधानिक निकाय है जिसे संसद द्वारा स्थापित किया गया है) 12 अप्रैल, 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया था। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।
- यह अर्ध-विधायी, अर्ध-न्यायिक और अर्ध-कार्यकारी निकाय के रूप में त्रिगुण कार्य करता है। अतः, कथन 2 सही है।
- प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम, 2014 द्वारा, सेबी अब 100 करोड़ रुपये की किसी भी मनी पूलिंग योजना को विनियमित करने में सक्षम है। या अधिक और गैर-अनुपालन के मामले में संपत्ति कुर्क करें। अतः, कथन 3 सही है।

51. उत्तर C
- भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिए मौजूदा योजनाओं के विलय के बाद यह एक नई योजना है। अतः, कथन 1 सही है।
- समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य के माध्यम से यह चयनित अस्पतालों के माध्यम से लिंग-पुनर्पुष्टि सर्जरी का समर्थन करने वाले प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के साथ मिलकर एक व्यापक पैकेज प्रदान करता है। अतः, कथन 2 सही है।

52. उत्तर A
- यह भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अतः, कथन 1 सही है।
- योजना का दायरा: यह योजना शुरू में 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए थी, लेकिन योजना का दायरा सभी भूमिधारक किसानों को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया था। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।
- भौतिक सत्यापन मॉड्यूल: योजना में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष 5% लाभार्थियों का अनिवार्य भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।

53. Answer B

- The FoF for Startups Scheme, established in June 2016 with a corpus of Rs. 10,000 Cr, aims to boost the Indian Startup ecosystem by spreading contributions over the 14th and 15th Finance Commission cycles based on implementation progress, facilitating access to domestic capital. Hence, statement 1 is not correct.
- SISF, approved for a four-year period from 2021-22 with a corpus of Rs. 945 Cr, provides financial aid to Startups for proof of concept, prototype development, product trials, market entry, and commercialisation. Hence, statement 2 is correct.
- Startup India Investor Connect facilitates AI-based matchmaking to connect startups with investors, streamlining the process for entrepreneurs to pitch their ideas to multiple investors through a single application. Hence, statement 3 is correct.

54. Answer B

- Statement 3 is incorrect: When exports exceed imports, there is a trade surplus.
- Statement 4 is incorrect: When imports exceed exports there is a trade deficit.

Balance of Payments (BoP)

- The balance of payments (BoP) records the transactions in goods, services and assets between residents of a country with the rest of the world for a specified time period typically a year. There are two main accounts in the BoP – the current account and the capital account.
- The current account records exports and imports in goods and services and transfer payments. When exports exceed imports, there is a trade surplus and when imports exceed exports there is a trade deficit.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

53. उत्तर B

- स्टार्टअप योजना के लिए FoF, जून 2016 में रुपये के कोष के साथ स्थापित किया गया था। 10,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य कार्यान्वयन प्रगति के आधार पर 14वें और 15वें वित्त आयोग चक्रों में योगदान फैलाकर, घरेलू पूंजी तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।
- एसआईएसएफ, रुपये के कोष के साथ 2021-22 से चार साल की अवधि के लिए अनुमोदित। 945 करोड़, अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अतः, कथन 2 सही है।
- स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट स्टार्टअप्स को निवेशकों से जोड़ने के लिए एआई-आधारित मैचमेकिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उद्यमियों के लिए एक ही एप्लिकेशन के माध्यम से कई निवेशकों तक अपने विचारों को पहुंचाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाता है। अतः, कथन 3 सही है।

54. उत्तर बी

- कथन 3 गलत है: जब निर्यात आयात से अधिक हो जाता है, तो व्यापार अधिशेष होता है।
- कथन 4 गलत है: जब आयात निर्यात से अधिक होता है तो व्यापार घाटा होता है।

भुगतान संतुलन (बीओपी)

- भुगतान संतुलन (बीओपी) किसी देश के निवासियों और शेष दुनिया के बीच एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए आमतौर पर एक वर्ष के लिए वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों में लेनदेन को रिकॉर्ड करता है। बीओपी में दो मुख्य खाते हैं - चालू खाता और पूंजी खाता।
- चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं में निर्यात और आयात और हस्तांतरण भुगतान को रिकॉर्ड करता है। जब निर्यात, आयात से अधिक हो जाता है, तो व्यापार अधिशेष होता है और जब आयात, निर्यात से अधिक हो जाता है, तो व्यापार घाटा होता है।

55. Answer A

BoP Surplus and Deficit

- The essence of international payments is that just like an individual who spends more than her income must finance the difference by selling assets or by borrowing, a country that has a deficit in its current account (spending more abroad than it receives from sales to the rest of the world) must finance it by selling assets or by borrowing abroad.
- Thus, any current account deficit is of necessity financed by a net capital inflow. Alternatively, the country could engage in official reserve transactions, running down its reserves of foreign exchange, in the case of a deficit by selling foreign currency in the foreign exchange market.
- The decrease (increase) in official reserves is called the overall balance of payments deficit (surplus). The basic premise is that the monetary authorities are the ultimate financiers of any deficit in the balance of payments (or the recipients of any surplus). The balance of payments deficit or surplus is obtained after adding the current and capital account balances.

56. Answer A

- Statement 3 is incorrect: PDI takes into account both earned income and transfer payments, while subtracting taxes and other deductions.
- PDI refers to the total income available to individuals or households after deducting taxes and other compulsory deductions. It represents the amount of money that individuals have at their disposal for spending, saving, and investing. PDI takes into account both earned income (such as salaries, wages, and business profits) and transfer payments (such as government benefits and subsidies), while subtracting taxes and other deductions.
- In India, Personal Disposable Income is an important economic indicator that refl ects the financial well-being of individuals and households

55. उत्तर ए

बीओपी अधिशेष और घाटा

- अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का सार यह है कि जैसे एक व्यक्ति जो अपनी आय से अधिक खर्च करता है, उसे संपत्ति बेचकर या उधार लेकर अंतर को पूरा करना होगा, एक देश जिसके चालू खाते में घाटा है (बाकी की बिक्री से प्राप्त होने की तुलना में विदेश में अधिक खर्च करना) दुनिया के) को संपत्ति बेचकर या विदेश में उधार लेकर इसे वित्तपोषित करना होगा।
- इस प्रकार, किसी भी चालू खाते के घाटे को शुद्ध पूंजी प्रवाह द्वारा वित्त पोषित करना आवश्यक है। वैकल्पिक रूप से, देश विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा बेचकर घाटे की स्थिति में, विदेशी मुद्रा के अपने भंडार को कम करते हुए, आधिकारिक आरक्षित लेनदेन में संलग्न हो सकता है।
- आधिकारिक भंडार में कमी (वृद्धि) को समग्र भुगतान संतुलन घाटा (अधिशेष) कहा जाता है। मूल आधार यह है कि मौद्रिक अधिकारी ही सर्वोपरि हैं भुगतान संतुलन में किसी भी घाटे के वित्तपोषक (या किसी अधिशेष के प्राप्तकर्ता)। भुगतान संतुलन घाटा या अधिशेष चालू और पूंजी खाते के शेष को जोड़ने के बाद प्राप्त किया जाता है।

56. उत्तर ए

- कथन 3 गलत है: पीडीआई करों और अन्य कटौतियों को घटाते समय अर्जित आय और हस्तांतरण भुगतान दोनों को ध्यान में रखता है।
- पीडीआई से तात्पर्य करों और अन्य अनिवार्य कटौतियों के बाद व्यक्तियों या परिवारों को उपलब्ध कुल आय से है। यह उस धन की मात्रा को दर्शाता है जो व्यक्तियों के पास खर्च करने, बचत करने और निवेश करने के लिए है। पीडीआई करों और अन्य कटौतियों को घटाते समय अर्जित आय (जैसे वेतन, मजदूरी और व्यावसायिक लाभ) और हस्तांतरण भुगतान (जैसे सरकारी लाभ और सब्सिडी) दोनों को ध्यान में रखता है।
- भारत में, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है जो व्यक्तियों और परिवारों की वित्तीय भलाई को दर्शाता है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

57. Answer C

- Pair 1 is incorrect: Gross National Income - It takes into account GDP along with net income from abroad.

National Income Accounting of India

- India employs a system of National Income Accounting that follows international standards, primarily based on the guidelines provided by the United Nations System of National Accounts (SNA). The central agency responsible for preparing and disseminating these accounts in India is the Central Statistics Office (CSO), which operates under the Ministry of Statistics and Programme Implementation.

Indicators of the National Income

- Accounting: Gross Domestic Product (GDP): GDP is one of the most essential measures in National Income Accounting. It represents the total value of all goods and services produced within the country's borders over a specific time period. India calculates GDP using three approaches: the production approach, the expenditure approach, and the income approach.
- Gross National Income (GNI): GNI takes into account GDP along with net income from abroad. It considers net primary income (wages, interest, profits, etc.) earned by Indian residents from foreign sources and subtracts net primary income paid to foreign residents.
- Gross Value Added (GVA): GVA is the value of goods and services produced within an industry, minus the value of intermediate consumption. It provides a measure of the contribution of each industry to the economy.
- Net National Income (NNI): NNI is derived by subtracting depreciation (wear and tear of capital goods) from GNI. It gives a better indication of the income available for consumption and investment.
- Net Domestic Product (NDP): NDP is obtained by subtracting depreciation from GDP. It represents the value of the country's net output of goods and services.

57. उत्तर सी

जोड़ी 1 गलत है: सकल राष्ट्रीय आय - इसमें विदेश से शुद्ध आय के साथ-साथ जीडीपी को भी ध्यान में रखा जाता है।

भारत का राष्ट्रीय आय लेखा

- भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन की एक प्रणाली कार्यरत है जो अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करती है, जो मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए) द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों पर आधारित है। भारत में इन खातों को तैयार करने और प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय एजेंसी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत काम करती है।

राष्ट्रीय आय के संकेतक

- लेखांकन: सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी): जीडीपी राष्ट्रीय आय लेखांकन में सबसे आवश्यक उपायों में से एक है। यह एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। भारत तीन दृष्टिकोणों का उपयोग करके सकल घरेलू उत्पाद की गणना करता है: उत्पादन दृष्टिकोण, व्यय दृष्टिकोण और आय दृष्टिकोण।
- सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई): जीएनआई विदेश से शुद्ध आय के साथ-साथ जीडीपी को भी ध्यान में रखता है। यह भारतीय निवासियों द्वारा विदेशी स्रोतों से अर्जित शुद्ध प्राथमिक आय (मजदूरी, ब्याज, लाभ, आदि) पर विचार करता है और विदेशी निवासियों को भुगतान की गई शुद्ध प्राथमिक आय को घटा देता है।
- सकल मूल्य वर्धित (जीवीए): जीवीए एक उद्योग के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, जिसमें मध्यवर्ती खपत का मूल्य घटा दिया जाता है। यह अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उद्योग के योगदान का माप प्रदान करता है।
- शुद्ध राष्ट्रीय आय (एनएनआई): एनएनआई जीएनआई से मूल्यह्रास (पूंजीगत वस्तुओं की टूट-फूट) घटाकर प्राप्त की जाती है। यह उपभोग और निवेश के लिए उपलब्ध आय का बेहतर संकेत देता है।
- शुद्ध घरेलू उत्पाद (एनडीपी): जीडीपी से मूल्यह्रास घटाकर एनडीपी प्राप्त किया जाता है। यह देश की वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध उत्पादन के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

58. Answer D

Corporate tax in India

- Corporate tax in India is a tax levied on the income earned by corporations or companies operating within the country. The tax is applied to the profits generated by these entities during a financial year.
- Corporate tax rates can vary based on factors such as the type of company, its annual turnover, and any applicable tax incentives or exemptions.
- In India, corporate tax rates can be different for domestic companies and foreign companies. The rates may also be influenced by the company's turnover or revenue. The government may revise these rates periodically through budget announcements.

59. Answer B

- Pair 1 is correct: Cash Reserve Ratio (CRR) - The fraction of their deposits which the commercial banks are required to keep with RBI.
- Pair 2 is correct: Depreciation - Wear and tear or depletion which capital stock undergoes over a period of time.
- Pair 3 is incorrect: Devaluation - The decrease in the price of domestic currency under pegged exchange rates through official action.

60. Answer B

- Statement 1 is incorrect: The relationship between inflation and unemployment is often described using the Phillips curve, which illustrates an inverse relationship between the two in the short run.
- Statement 4 is incorrect: Central banks often use monetary policy tools, such as raising interest rates, to control inflation.

Cost-Push Inflation

- Inflation can be caused by factors such as rising commodity prices, supply disruptions, or increases in production costs. When the cost of production rises, businesses may cut back on production and reduce their workforce to maintain profitability. This can result in higher unemployment rates, as businesses adjust their operations in response to increased costs.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

58. उत्तर डी

भारत में कॉर्पोरेट टैक्स

- भारत में कॉर्पोरेट टैक्स देश के भीतर संचालित निगमों या कंपनियों द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाने वाला कर है। कर एक वित्तीय वर्ष के दौरान इन संस्थाओं द्वारा उत्पन्न मुनाफे पर लागू होता है।
- कॉर्पोरेट कर की दरें कंपनी के प्रकार, उसके वार्षिक कारोबार और किसी भी लागू कर प्रोत्साहन या छूट जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती हैं।
- भारत में घरेलू कंपनियों और विदेशी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दरें अलग-अलग हो सकती हैं। दरें भी हो सकती हैं
- कंपनी के टर्नओवर या राजस्व से प्रभावित। सरकार बजट घोषणाओं के माध्यम से इन दरों को समय-समय पर संशोधित कर सकती है।

59. उत्तर बी

- जोड़ी 1 सही है: नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) - अपनी जमा राशि का वह अंश जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना आवश्यक है।
- जोड़ी 2 सही है: मूल्यह्रास - समय के साथ पूंजीगत स्टॉक में टूट-फूट या कमी आती है।
- जोड़ी 3 गलत है: अवमूल्यन - आधिकारिक कार्रवाई के माध्यम से आंकी गई विनिमय दरों के तहत घरेलू मुद्रा की कीमत में कमी।

60. उत्तर बी

- कथन 1 गलत है: मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को अक्सर फिलिप्स वक्र का उपयोग करके वर्णित किया जाता है, जो अल्पावधि में दोनों के बीच एक विपरीत संबंध को दर्शाता है।
- कथन 4 गलत है: मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक अक्सर मौद्रिक नीति उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे ब्याज दरें बढ़ाना।

लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति

- मुद्रास्फीति कमोडिटी की बढ़ती कीमतों, आपूर्ति में व्यवधान या उत्पादन लागत में वृद्धि जैसे कारकों के कारण हो सकती है। जब उत्पादन की लागत बढ़ती है, तो व्यवसाय लाभप्रदता बनाए रखने के लिए उत्पादन में कटौती कर सकते हैं और अपने कार्यबल को कम कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप उच्च बेरोजगारी दर हो सकती है, क्योंकि व्यवसाय बढ़ी हुई लागत के जवाब में अपने संचालन को समायोजित करते हैं।

ALIGANJ | INDIRA NAGAR | ALAMBAGH, LUCKNOW & KANPUR
WEBSITE :www.raceias.com, /raceiaslucknow
E-mail ID : www.raceias.2010@gmail.com
8917851448
MOCK TEST EXPLANATIONS
RACE IAS

Reduced Consumer Spending

- High inflation erodes the purchasing power of consumers. When prices rise rapidly, consumers may cut back on discretionary spending and focus on essential goods and services.
- This reduction in consumer spending can lead to reduced demand for various products, which in turn can cause businesses to cut back on production and employment.

61. Answer D

Mixed economy

- The Mixed Economy is a system that combines capitalism and socialism. The Mixed Economy incorporates the benefits of capitalism and socialism while avoiding their drawbacks.
- Under a Mixed Economy, the private and public sector coexist. (sometimes in similar structure).

Features of a Mixed Economy

- Freedom and Control: To be precise, in a Mixed Economy, we denote that the individuals have complete liberty to manufacture goods and items and choose property and occupation according to their choice. The regulating body maintains control to avoid all sorts of discrimination and monopolistic issues.
- Economic Planning: In a Mixed Economy, the central planning authority exists. All the sectors of the firm follow this rule and plan to pursue their goals. The plan is solely observed with the motive to attain national Economic growth.
- Cooperative Sector: According to the Mixed Economy definition, a cooperative sector exists in a Mixed Economy.
- In Mixed Economy countries, the government provides necessary items and financial aids to the areas involved in cooperative societies like warehousing, dairy industry and more.

उपभोक्ता खर्च में कमी

- उच्च मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को नष्ट कर देती है। जब कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तो उपभोक्ता विवेकाधीन खर्च में कटौती कर सकते हैं और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
- उपभोक्ता खर्च में इस कमी से विभिन्न उत्पादों की मांग कम हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप व्यवसायों को उत्पादन और रोजगार में कटौती करनी पड़ सकती है।

61. उत्तर डी

मिश्रित अर्थव्यवस्था

- मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो पूंजीवाद और समाजवाद को जोड़ती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद की कमियों से बचते हुए उनके लाभों को शामिल करती है।
- मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र सह-अस्तित्व में हैं। (कभी-कभी समान संरचना में)।

मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं

- स्वतंत्रता और नियंत्रण: सटीक रूप से कहें तो, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, हम दर्शाते हैं कि व्यक्तियों को वस्तुओं और वस्तुओं का निर्माण करने और अपनी पसंद के अनुसार संपत्ति और व्यवसाय चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है। नियामक निकाय सभी प्रकार के भेदभाव और एकाधिकार संबंधी मुद्दों से बचने के लिए नियंत्रण बनाए रखता है।
- आर्थिक नियोजन: मिश्रित अर्थव्यवस्था में, केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण मौजूद होता है। फर्म के सभी क्षेत्र इस नियम का पालन करते हैं और अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की योजना बनाते हैं। यह योजना पूरी तरह से राष्ट्रीय आर्थिक विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से देखी गई है।
- सहकारी क्षेत्र: मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा के अनुसार, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक सहकारी क्षेत्र मौजूद होता है।
- मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में, सरकार सहकारी समितियों जैसे भंडारण, डेयरी उद्योग और अन्य क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

62. Answer C

Demand Curve

- A demand curve is almost always downward-sloping, reflecting the willingness of consumers to purchase more of the commodity at lower price levels.
- Any change in non-price factors would cause a shift in the demand curve, whereas changes in the price of the commodity can be traced along a fixed demand curve.
- The quantity of a commodity demanded depends on the price of that commodity and potentially on many other factors, such as the prices of other commodities, the incomes and preferences of consumers, and seasonal effects.

63. Answer A

- Option (a) is correct: A Giffen good is a low-income, non-luxury product for which demand increases as the price increases and vice versa.
- Giffen Goods A Giffen good has an upward-sloping demand curve which is contrary to the fundamental laws of demand which are based on a downward sloping demand curve.
- Demand for Giffen goods is heavily influenced by a lack of close substitutes and income pressures. Veblen goods are similar to Giffen goods but with a focus on luxury items.

64. Answer C

- Statement 1 is incorrect: NEER and REER were calculated for the first time post the 1991 reforms.
- Statement 2 is correct: The crisis, and a series of domestic scams, helped bring home the lesson that excessive interest controls and credit rationing were deleterious to and stability. The RBI itself noted monetary policy based on demand function of money, as the latter became unstable, could be expected to lack precision.
- After the adverse impact of the 1990s' peak in interest rates, the Reserve Bank moved toward an interest rate based operating procedure, basing its actions on a number of indicators of monetary conditions, including forward-looking expectation surveys. It formally adopted a "multiple-indicator approach" in April 1998, following informal changes in practice from the mid-1990.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

62. उत्तर सी

मांग वक्र

- मांग वक्र लगभग हमेशा नीचे की ओर झुका हुआ होता है, जो उपभोक्ताओं की कम कीमत के स्तर पर अधिक वस्तु खरीदने की इच्छा को दर्शाता है।
- गैर-मूल्य कारकों में कोई भी बदलाव मांग वक्र में बदलाव का कारण बनेगा, जबकि वस्तु की कीमत में बदलाव को एक निश्चित मांग वक्र के साथ पता लगाया जा सकता है।
- किसी वस्तु की मांग की मात्रा उस वस्तु की कीमत और संभावित रूप से कई अन्य कारकों पर निर्भर करती है, जैसे अन्य वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ताओं की आय और प्राथमिकताएं, और मौसमी प्रभाव।

63. उत्तर ए

- विकल्प (ए) सही है: गिफेन वस्तु एक कम आय वाला, गैर-लक्जरी उत्पाद है जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और इसके विपरीत।
- गिफेन वस्तुएँ गिफेन वस्तु में ऊपर की ओर झुका हुआ मांग वक्र होता है जो मांग के मूलभूत नियमों के विपरीत होता है जो नीचे की ओर झुके हुए मांग वक्र पर आधारित होते हैं।
- गिफेन वस्तुओं की मांग करीबी विकल्प की कमी और आय के दबाव से काफी प्रभावित होती है। वेब्लेन वस्तुएं गिफेन वस्तुओं के समान होती हैं लेकिन लक्जरी वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

64. उत्तर C

- कथन 1 ग़लत है: एनईईआर और आरईईआर की गणना 1991 के सुधारों के बाद पहली बार की गई थी।
- कथन 2 सही है: संकट और घरेलू घोटालों की एक श्रृंखला ने यह सबक देने में मदद की कि अत्यधिक ब्याज नियंत्रण और क्रेडिट राशनिंग स्थिरता के लिए हानिकारक थे। आरबीआई ने स्वयं नोट किया कि मुद्रा की मांग के आधार पर मौद्रिक नीति अस्थिर हो गई है, जिससे सटीकता की कमी की उम्मीद की जा सकती है।
- 1990 के दशक में ब्याज दरों में चरम के प्रतिकूल प्रभाव के बाद, रिज़र्व बैंक ने भविष्योन्मुखी अपेक्षा सर्वेक्षणों सहित मौद्रिक स्थितियों के कई संकेतकों पर अपने कार्यों को आधार बनाते हुए, ब्याज दर आधारित परिचालन प्रक्रिया की ओर कदम बढ़ाया। 1990 के मध्य से व्यवहार में अनौपचारिक परिवर्तनों के बाद, अप्रैल 1998 में इसने औपचारिक रूप से "बहु-संकेतक दृष्टिकोण" अपनाया।

ALIGANJ | INDIRA NAGAR | ALAMBAGH, LUCKNOW & KANPUR
WEBSITE :www.raceias.com, /raceiaslucknow
E-mail ID : www.raceias.2010@gmail.com
8917851448
MOCK TEST EXPLANATIONS
RACE IAS

65. Answer D
- Statement 1 is correct: The institutional framework within which monetary policy operated underwent several changes. The most important change was the phasing out of the system of the issue of ad hoc treasury bills by the government to the RBI. The automatic monetization of the government deficit was stopped and auction-based market borrowing adopted for meeting the fiscal deficits. The repressed financial regime was dismantled, interest rates became more market determined, and the government began to borrow at market rates.
- Statement 2 is incorrect: The Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003, put an end to the RBI entering the primary market in government securities.

66. Answer B
- Statement 1 is incorrect: M3 is the most commonly used measure of money supply, also known as Aggregate Monetary. Resources / Aggregate Money Supply" because out of all the money supply indicators (M0-M4) this is the indicator RBI will focus the most for its analysis while designing monetary policy.
- Statement 2 is correct: In above formulas for money supply, RBI only calculates the "NET Demand / NET Time deposits" i.e. only the public's deposits in banks. We are not counting Interbank deposits i.e. one commercial bank's deposit in other commercial banks.
- Statement 3 is correct: M1 and M2 are called Narrow money. Because of their smaller size (since they only cover demand deposits) M3 and M4 are called broad money, because of their relatively larger size than M1 and M2.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

65. उत्तर D
- कथन 1 सही है: संस्थागत ढांचा जिसके अंतर्गत मौद्रिक नीति संचालित होती है, उसमें कई बदलाव हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन सरकार द्वारा आरबीआई को तदर्थ ट्रेजरी बिल जारी करने की प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था। सरकारी घाटे का स्वचालित मुद्रीकरण रोक दिया गया और राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए नीलामी-आधारित बाजार उधार को अपनाया गया। दमित वित्तीय व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, ब्याज दरें अधिक बाजार निर्धारित हो गईं, और सरकार ने बाजार दरों पर उधार लेना शुरू कर दिया।
- कथन 2 गलत है: राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003, सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक बाजार में प्रवेश करने वाले आरबीआई को समाप्त कर देता है।

66. उत्तर B
- कथन 1 गलत है: एम3 मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है, जिसे समग्र मौद्रिक के रूप में भी जाना जाता है। संसाधन / समग्र धन आपूर्ति" क्योंकि सभी धन आपूर्ति संकेतकों (एम0-एम4) में से यह वह संकेतक है जो आरबीआई मौद्रिक नीति को डिजाइन करते समय अपने विश्लेषण के लिए सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करेगा।
- कथन 2 सही है: धन आपूर्ति के लिए उपरोक्त सूत्रों में, आरबीआई केवल "नेट डिमांड / नेट टाइम डिपॉजिट" की गणना करता है, अर्थात बैंकों में केवल जनता की जमा राशि। हम इंटरबैंक जमाओं की गिनती नहीं कर रहे हैं यानी एक वाणिज्यिक बैंक की अन्य वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि।
- कथन 3 सही है: M1 और M2 को नैरो मनी कहा जाता है। उनके छोटे आकार के कारण (चूंकि वे केवल मांग जमा को कवर करते हैं) एम3 और एम4 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि एम1 और एम2 की तुलना में उनका आकार अपेक्षाकृत बड़ा है।

67. Answer B

- Statement 1 is incorrect: The objective of the monetary policy is to achieve price stability keeping in mind the objective of Growth.
- Statement 2 is correct: The RBI Act 1934 provides for the inflation target to be set by the government of India, in consultation with the Reserve Bank, once in every five years.
- Statement 3 is correct: The inflation target is decided by the Government of India in consultation with RBI. The central government has notified the above inflation target for the period till March 31, 2026.

68. Answer D

- Statement 1 is incorrect: Money Multiplier is the ratio of total money supply to the stock of high powered money in an economy. Reserve deposit ratio is the fraction of their total deposits which commercial banks keep as reserves
- Statement 2 is incorrect: Currency Deposit Ratio (cdr) = Ratio of Currency held by Public to Deposits of public in banks. cdr equal to 1 means whenever an individual gets some amount of cash, say Rs.100, then he will keep Rs.50 as cash and Rs.50 as deposit in banks, so that the ratio of cash in hand and deposits in banks is Rs.50/Rs.50 = 1.
- Statement 3 is correct: Reserve Deposit Ratio (rdr) = Ratio of Reserves of Banks to the Deposits of public in banks. RDR equals 0.2 or 20% means whenever an individual deposits a certain sum of money, say Rs.100 with the bank, the bank will have to keep Rs.20 as reserve money and the rest Rs.80 they can lend to someone else. Banks can keep the reserves either with themselves (SLR) or with RBI (CRR). So, rdr is the sum of CRR and SLR.
- Statement 4 is correct: In a functional economy, Money multiplier (MM) is always greater than 1 & CRR will always be less than 100%. MM directly improves with reduction in CRR MM indirectly improves as the economy develops, consumption / loan demand increases, banking penetration, digital economy/less-cash economy etc.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

67. उत्तर B

- कथन 1 गलत है: मौद्रिक नीति का उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता प्राप्त करना है।
- कथन 2 सही है: आरबीआई अधिनियम 1934 में हर पांच साल में एक बार रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान है।
- कथन 3 सही है: मुद्रास्फीति लक्ष्य आरबीआई के परामर्श से भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए उपरोक्त मुद्रास्फीति लक्ष्य को अधिसूचित किया है।

68. उत्तर डी

- कथन 1 गलत है: मनी मल्टीप्लायर एक अर्थव्यवस्था में उच्च शक्ति वाले पैसे के स्टॉक के लिए कुल धन आपूर्ति का अनुपात है। आरक्षित जमा अनुपात उनकी कुल जमा राशि का वह अंश है जिसे वाणिज्यिक बैंक आरक्षित निधि के रूप में रखते हैं।
- कथन 2 गलत है: मुद्रा जमा अनुपात (सीडीआर) = जनता द्वारा बैंकों में जमा की गई मुद्रा का अनुपात। सीडीआर 1 के बराबर होने का मतलब है कि जब भी किसी व्यक्ति को कुछ मात्रा में नकदी मिलती है, मान लीजिए 100 रुपये, तो वह 50 रुपये नकद और 50 रुपये बैंकों में जमा के रूप में रखेगा, ताकि हाथ में नकदी और बैंकों में जमा का अनुपात हो। रु.50/रु.50 = 1.
- कथन 3 सही है: आरक्षित जमा अनुपात (आरडीआर) = बैंकों के आरक्षित भंडार का बैंकों में जनता की जमा राशि से अनुपात। आरडीआर 0.2 या 20% के बराबर होता है, इसका मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति बैंक में एक निश्चित राशि, मान लीजिए 100 रुपये जमा करता है, तो बैंक को 20 रुपये आरक्षित धन के रूप में रखना होगा और शेष 80 रुपये वे किसी और को उधार दे सकते हैं। बैंक रिजर्व को या तो अपने पास (एसएलआर) या आरबीआई (सीआरआर) के पास रख सकते हैं। तो, आरडीआर सीआरआर और एसएलआर का योग है।
- कथन 4 सही है: एक कार्यात्मक अर्थव्यवस्था में, धन गुणक (एमएम) हमेशा 1 से अधिक होता है और सीआरआर हमेशा 100% से कम होगा। सीआरआर में कमी के साथ एमएम में प्रत्यक्ष रूप से सुधार होता है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, उपभोग/ऋण की मांग बढ़ती है, बैंकिंग पैठ, डिजिटल अर्थव्यवस्था/कम-नकदी अर्थव्यवस्था आदि होती है, एमएम में अप्रत्यक्ष रूप से सुधार होता है।

69. Answer D

- Statement 1 is incorrect: As per section 24 of RBI Act 1934, "Central Government, on the recommendation of the Central Board of Directors of RBI, has the authority to specify the denomination of the new currency note to be issued in the country.
- Statement 2 is incorrect : As per the RBI Act 1934, Section 25, "the design, form and material of bank notes shall be such as may be approved by the Central Government after consideration of the recommendations made by the Central Board of RBI
- Statement 3 is incorrect: As per the RBI Act 1934, Section 26, "on recommendation of the Central Board, the Central Government may, by notification in the Gazette of India, declare that, with effect from such date, any series of bank notes of any denomination shall cease to be legal tender.

69. उत्तर D

- कथन 1 गलत है: RBI अधिनियम 1934 की धारा 24 के अनुसार, "केंद्र सरकार, RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल की सिफारिश पर, देश में जारी किए जाने वाले नए मुद्रा नोट के मूल्य को निर्दिष्ट करने का अधिकार रखती है।
- कथन 2 गलत है: आरबीआई अधिनियम 1934, धारा 25 के अनुसार, "बैंक नोटों का डिज़ाइन, रूप और सामग्री ऐसी होगी जिसे आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।
- कथन 3 गलत है: आरबीआई अधिनियम 1934, धारा 26 के अनुसार, "केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर, केंद्र सरकार, भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकती है कि, ऐसी तारीख से, बैंक नोटों की कोई भी श्रृंखला किसी भी मूल्यवर्ग की कानूनी निविदा नहीं रहेगी।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations
RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

70. Answer B

- Statement 1 is incorrect: This is a function of being Banker to Banks and not central Government. The current accounts of individual banks are being opened in e-Kuber (CBS of RBI) by Banking Departments of the Regional Offices. These current accounts are also maintained for participation in Centralized and decentralized Payment Systems and are used for settling inter-bank obligations, such as clearing transactions or clearing money market transactions between two banks, buying and selling securities and foreign currencies. The Reserve Bank stipulates minimum balances to be maintained by banks in these accounts.
- Statement 2 is correct: The RBI acts as advisor to the Government, whenever called upon to do so, on monetary and banking related matters.
- Statement 3 is correct: RBI also provides "Ways and Means Advances" (WMA) – it is a temporary loan facility to the Centre and state/UT governments as a banker to the government. Besides it arranges for investments of surplus cash balances of the Governments as a portfolio manager.
- Statement 4 is incorrect: When RBI floates/raises loans on behalf of the government then it is acting as a "Debt Manager" of the government and not as a Banker to the government. The RBI manages the public debt and issues new loans on behalf of the Central and State Governments. The RBI's debt management policy aims at minimizing the cost of borrowing, reducing risk, smoothening the maturity structure of debt.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

70. उत्तर B

- कथन 1 गलत है: यह बैंकों का बैंकर होने का कार्य है, केंद्र सरकार का नहीं। क्षेत्रीय कार्यालयों के बैंकिंग विभागों द्वारा व्यक्तिगत बैंकों के चालू खाते ई-कुबेर (आरबीआई के सीबीएस) में खोले जा रहे हैं। ये चालू खाते केंद्रीकृत और विकेन्द्रीकृत भुगतान प्रणालियों में भागीदारी के लिए भी बनाए रखे जाते हैं और अंतर-बैंक दायित्वों को निपटाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे लेनदेन को साफ़ करना या दो बैंकों के बीच मुद्रा बाजार लेनदेन को साफ़ करना, प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्राओं को खरीदना और बेचना। रिज़र्व बैंक इन खातों में बैंकों द्वारा बनाए रखा जाने वाला न्यूनतम शेष निर्धारित करता है।
- कथन 2 सही है: जब भी आरबीआई को ऐसा करने के लिए कहा जाता है, वह मौद्रिक और बैंकिंग संबंधी मामलों पर सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
- कथन 3 सही है: RBI "वेज़ एंड मीन्स एडवांसेज" (WMA) भी प्रदान करता है - यह सरकार के बैंकर के रूप में केंद्र और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को एक अस्थायी ऋण सुविधा है। इसके अलावा यह एक पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में सरकार के अधिशेष नकदी शेष के निवेश की व्यवस्था करता है।
- कथन 4 गलत है: जब आरबीआई सरकार की ओर से ऋण जारी/उठाता है तो वह सरकार के "ऋण प्रबंधक" के रूप में कार्य कर रहा है, न कि सरकार के बैंकर के रूप में। आरबीआई सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करता है और केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से नए ऋण जारी करता है। आरबीआई की ऋण प्रबंधन नीति का उद्देश्य उधार लेने की लागत को कम करना, जोखिम को कम करना, ऋण की परिपक्वता संरचना को सुचारू बनाना है।

71. Answer A
- Statement 1 is correct: The Reserve Bank of India gives temporary loan facilities to the centre and state governments as a banker to the government. This temporary loan facility is called Ways and Means Advances (WMA). The WMA scheme was designed to meet temporary mismatches in the receipts and payments of the government. This facility can be availed by the government if it needs immediate cash from the RBI.
- Statement 2 is correct: The WMA is a loan facility from the RBI for 90 days which implies that the government has to vacate the facility after 90 days. Interest rate for WMA is currently charged at the repo rate. The limits for WMA are mutually decided by the RBI and the Government of India.
- Statement 3 is incorrect: It is the Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBMA), 2003 and not RBI Act which stipulates that the GoI cannot borrow from RBI except by Ways and Means Advances (WMAs) and not the RBI Act.

72. Answer D
- Statement 1 is correct: The amount of reserves that the scheduled commercial banks are required to maintain with themselves on a daily basis in safe and liquid assets such as government securities, gold and cash with respect to their NDTL is called SLR.
- Statement 2 is correct: In contrast to the CRR, under which banks have to maintain cash with the RBI, the SLR requires holding of assets by the bank itself.
- Statement 3 is correct: For scheduled banks, the maintenance of CRR is governed through The Reserve Bank of India Act 1934 and for Non-Scheduled banks CRR is governed through Banking Regulation Act 1949. Banking Regulation Act 1949 (Section 24) governs maintenance of SLR for all banks (scheduled and non-scheduled) commercial and cooperative.
- Statement 4 is correct: Excess CRR balances are also treated as liquid assets for the purpose of SLR i.e., SLR can be maintained as cash balance with RBI.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

71. उत्तर ए
- कथन 1 सही है: भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के बैंकर के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों को अस्थायी ऋण सुविधाएं देता है। इस अस्थायी ऋण सुविधा को वेज एंड मीन्स एडवांस (डब्ल्यूएमए) कहा जाता है। WMA योजना सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों में अस्थायी विसंगतियों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। अगर सरकार को आरबीआई से तत्काल नकदी की जरूरत है तो इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।
- कथन 2 सही है: डब्ल्यूएमए आरबीआई से 90 दिनों के लिए एक ऋण सुविधा है जिसका अर्थ है कि सरकार को 90 दिनों के बाद यह सुविधा खाली करनी होगी। WMA के लिए ब्याज दर वर्तमान में रेपो दर पर ली जाती है। WMA की सीमाएँ RBI और भारत सरकार द्वारा पारस्परिक रूप से तय की जाती हैं।
- कथन 3 गलत है: यह राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएमए), 2003 है, न कि आरबीआई अधिनियम जो यह निर्धारित करता है कि भारत सरकार आरबीआई से वेज एंड मीन्स एडवांस (डब्ल्यूएमए) के अलावा उधार नहीं ले सकती है, न कि आरबीआई अधिनियम।

72. उत्तर D
- कथन 1 सही है: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने एनडीटीएल के संबंध में सरकारी प्रतिभूतियों, सोना और नकदी जैसी सुरक्षित और तरल संपत्तियों में दैनिक आधार पर अपने पास आरक्षित राशि बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसे एसएलआर कहा जाता है।
- कथन 2 सही है: सीआरआर के विपरीत, जिसके तहत बैंकों को आरबीआई के पास नकदी बनाए रखनी होती है, एसएलआर के लिए बैंक द्वारा ही संपत्ति रखने की आवश्यकता होती है।
- कथन 3 सही है: अनुसूचित बैंकों के लिए, सीआरआर का रखरखाव भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के माध्यम से नियंत्रित होता है और गैर-अनुसूचित बैंकों के लिए सीआरआर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के माध्यम से नियंत्रित होता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (धारा 24) एसएलआर के रखरखाव को नियंत्रित करता है। सभी बैंकों (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित) वाणिज्यिक और सहकारी के लिए।
- कथन 4 सही है: अतिरिक्त सीआरआर शेष को एसएलआर के उद्देश्य के लिए तरल संपत्ति के रूप में भी माना जाता है, अर्थात, एसएलआर को आरबीआई के साथ नकद शेष के रूप में बनाए रखा जा सकता है।

73. Answer A
- Statement 1 is correct: The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) introduced a leverage ratio in the 2010 Basel III package of reforms.
- The leverage ratio is defined as the capital measure divided by the exposure measure, expressed as a percentage.
- The leverage ratio measures a bank's core capital to its total assets. The ratio uses tier 1 capital to judge how leveraged a bank is in relation to its consolidated assets.
- Statement 2 is incorrect: Minimum Leverage Ratio of banks is decided by the Reserve Bank of India (RBI). The RBI in 2019 relaxed the leverage ratio (LR) for banks in a bid to help them expand their lending activities. The leverage ratio stands reduced to 4% for Domestic Systemically Important Banks (DSIBs) and 3.5% for other banks. Leverage ratio is also one the four indicators under the RBI's Prompt Corrective Action framework.
- Statement 3 is correct: The higher the tier 1 leverage ratio, the higher the likelihood of the bank withstanding negative shocks to its balance sheet. However, a higher LR will reduce bank's lending capacity. Relaxation in LR for banks will help them in expanding their lending activities.

74. Answer C
- Current Account Deficit is a measurement of a country's trade in which the value of goods and services it imports exceeds the value of goods and services it exports. Hence Statement 1 is correct
- If a current account deficit is financed through borrowing it is said to be more unsustainable.This is because borrowing is unsustainable in the long term and countries will be burdened with high interest payments. Hence Statement 2 is correct
- A current account deficit may imply that you are relying on consumer spending, and are becoming uncompetitive. Hence Statement 3 is correct

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

73. उत्तर ए
- कथन 1 सही है: बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) ने सुधारों के 2010 बेसल III पैकेज में एक उत्तोलन अनुपात पेश किया।
- उत्तोलन अनुपात को एक्सपोज़र माप द्वारा विभाजित पूंजी माप के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है।
- उत्तोलन अनुपात किसी बैंक की मूल पूंजी को उसकी कुल संपत्ति से मापता है। यह अनुपात यह निर्धारित करने के लिए टियर 1 पूंजी का उपयोग करता है कि कोई बैंक अपनी समेकित परिसंपत्तियों के संबंध में कितना उत्तोलनशील है।
- कथन 2 गलत है: बैंकों का न्यूनतम उत्तोलन अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा तय किया जाता है। आरबीआई ने 2019 में बैंकों को उनकी ऋण गतिविधियों का विस्तार करने में मदद करने के लिए उत्तोलन अनुपात (एलआर) में ढील दी। घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (डीएसआईबी) के लिए उत्तोलन अनुपात घटाकर 4% और अन्य बैंकों के लिए 3.5% कर दिया गया है। उत्तोलन अनुपात भी आरबीआई के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे के तहत चार संकेतकों में से एक है।
- कथन 3 सही है: टियर 1 उत्तोलन अनुपात जितना अधिक होगा, बैंक की बैलेंस शीट पर नकारात्मक झटके झेलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। हालाँकि, अधिक LR से बैंक की ऋण देने की क्षमता कम हो जाएगी। बैंकों के लिए एलआर में छूट से उन्हें अपनी ऋण गतिविधियों का विस्तार करने में मदद मिलेगी।

74. उत्तर सी
- चालू खाता घाटा किसी देश के व्यापार का एक माप है जिसमें आयातित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से अधिक होता है। अतः कथन 1 सही है
- यदि चालू खाते के घाटे को उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है तो इसे अधिक अस्थिर कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लंबी अवधि में उधार लेना अस्थिर है और देशों पर उच्च ब्याज भुगतान का बोझ पड़ेगा। अतः कथन 2 सही है
- चालू खाते के घाटे का मतलब यह हो सकता है कि आप उपभोक्ता खर्च पर निर्भर हैं और अप्रतिस्पर्धी होते जा रहे हैं। अतः कथन 3 सही है

75. Answer B
- The percentage of cash required to be kept in reserves, vis-a-vis a bank's total deposits, is called the Cash Reserve Ratio. The Cash Reserve Ratio in India is decided by RBI's Monetary Policy Committee in the periodic Monetary and Credit Policy. Hence Statement 1 is correct.
- CRR is one of the major weapons in the RBI's arsenal that allows it to maintain a desired level of inflation, control the money supply, and also liquidity in the economy. Hence Statement 2 is correct.
- The cash reserve is either stored in the bank's vault or is sent to the RBI. Banks do not get any interest on the money that is with the RBI under the CRR requirements. Hence Statement 3 is incorrect.

76. Answer B
- ATMs set up, owned and operated by non-bank entities are called white label ATMs. Hence Statement 1 is correct.
- Cash in ATMs is provided by the sponsored bank while the ATM machine does not have any branding of the Bank. These white label ATMs will not display the logo of any particular bank. Hence Statement 2 is correct
- The operators are entitled to receive a fee from the banks for the use of ATM resources by the bank's customers and are not permitted to charge bank customers directly. Hence Statement 3 is incorrect

77. Answer C
- India's first UPI-ATM was launched as a White Label ATM (WLA) by Hitachi Payment Services.
- The UPI-ATM service, also known as Interoperable Cardless Cash Withdrawal (ICCW),
- The launch of the UPI-ATM is a significant development in the Indian payments landscape.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

75. उत्तर बी
- बैंक की कुल जमा राशि की तुलना में आरक्षित निधि में रखे जाने वाले नकदी के प्रतिशत को नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। भारत में नकद आरक्षित अनुपात आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा आवधिक मौद्रिक और क्रेडिट नीति में तय किया जाता है। अतः कथन 1 सही है।
- सीआरआर आरबीआई के शस्त्रागार में प्रमुख हथियारों में से एक है जो इसे मुद्रास्फीति के वांछित स्तर को बनाए रखने, धन आपूर्ति को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। अतः कथन 2 सही है।
- नकद रिजर्व या तो बैंक की तिजोरी में संग्रहीत किया जाता है या आरबीआई को भेजा जाता है। सीआरआर आवश्यकताओं के तहत आरबीआई के पास जो पैसा है उस पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता है। इसलिए कथन 3 गलत है।

76. उत्तर बी
- गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा स्थापित, स्वामित्व और संचालित एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। अतः कथन 1 सही है।
- एटीएम में नकदी प्रायोजित बैंक द्वारा प्रदान की जाती है जबकि एटीएम मशीन पर बैंक की कोई ब्रांडिंग नहीं होती है। इन व्हाइट लेबल एटीएम पर किसी विशेष बैंक का लोगो प्रदर्शित नहीं होगा। अतः कथन 2 सही है
- ऑपरेटर बैंक के ग्राहकों द्वारा एटीएम संसाधनों के उपयोग के लिए बैंकों से शुल्क प्राप्त करने के हकदार हैं और उन्हें बैंक ग्राहकों से सीधे शुल्क लेने की अनुमति नहीं है। इसलिए कथन 3 गलत है

77. उत्तर सी
- भारत का पहला UPI-ATM हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा व्हाइट लेबल एटीएम (WLA) के रूप में लॉन्च किया गया था।
- UPI-ATM सेवा, जिसे इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विदड्रॉल (ICCW) के रूप में भी जाना जाता है,
- यूपीआई-एटीएम का लॉन्च भारतीय भुगतान परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण विकास है।

78. Answer B

- Residual unemployment refers to those who remained unemployed even in times of full employment (for example, employing a severely handicapped person may far outweigh the productivity obtained from him).

o Whereas, Disguised unemployment is unemployment that does not affect aggregate economic output.

It occurs when low productivity and too many workers fill too few jobs. It can refer to any part of the population that is not employed at full capacity. Hence, statement 3 is not correct.

79. Answer C

- AIFs are privately pooled investment vehicles that are not permitted to make an invitation to the public to subscribe to its securities. AIFs shall raise funds through private placement by the issue of an information memorandum or placement memorandum, by whatever name is called. Hence, statement 1 is correct.
- A hedge fund is a limited partnership of private investors whose money is managed by professional fund managers who use a wide range of strategies, including leveraging or trading non-traditional assets, to earn above-average investment returns. Hedge fund investment is often considered a risky alternative investment choice and usually requires a high minimum investment or net worth, often targeting wealthy clients. Hence, statement 2 is correct.
- In this regard, it is clarified that, since an Alternative Investment Fund is a privately pooled investment vehicle, the amount contributed by the investors shall not be utilized for the purpose of giving loans. Hence, statement 3 is correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

78. उत्तर बी

- अवशिष्ट बेरोजगारी से तात्पर्य उन लोगों से है जो पूर्ण रोजगार के समय भी बेरोजगार रहते हैं (उदाहरण के लिए, किसी गंभीर रूप से विकलांग व्यक्ति को रोजगार देना उससे प्राप्त उत्पादकता से कहीं अधिक हो सकता है)।

o जबकि, प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो कुल आर्थिक उत्पादन को प्रभावित नहीं करती है।

यह तब होता है जब कम उत्पादकता और बहुत अधिक कर्मचारी बहुत कम नौकरियों को भरते हैं। यह जनसंख्या के किसी भी हिस्से को संदर्भित कर सकता है जो पूरी क्षमता से कार्यरत नहीं है। इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।

79. उत्तर सी

- एआईएफ निजी तौर पर एकत्रित निवेश साधन हैं जिन्हें अपनी प्रतिभूतियों की सदस्यता के लिए जनता को निमंत्रण देने की अनुमति नहीं है। एआईएफ निजी प्लेसमेंट के माध्यम से सूचना ज्ञापन या प्लेसमेंट ज्ञापन, चाहे जिसे भी नाम दिया जाए, जारी करके धन जुटाएगा। अतः, कथन 1 सही है।
- हेज फंड निजी निवेशकों की एक सीमित साझेदारी है, जिनके पैसे का प्रबंधन पेशेवर फंड प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, जो औसत निवेश रिटर्न अर्जित करने के लिए गैर-पारंपरिक परिसंपत्तियों का लाभ उठाने या व्यापार करने सहित कई रणनीतियों का उपयोग करते हैं। हेज फंड निवेश को अक्सर एक जोखिम भरा वैकल्पिक निवेश विकल्प माना जाता है और इसके लिए आमतौर पर उच्च न्यूनतम निवेश या निवल मूल्य की आवश्यकता होती है, जो अक्सर धनी ग्राहकों को लक्षित करता है। अतः, कथन 2 सही है।
- इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि, चूंकि वैकल्पिक निवेश कोष एक निजी तौर पर एकत्रित निवेश माध्यम है, इसलिए निवेशकों द्वारा योगदान की गई राशि का उपयोग ऋण देने के उद्देश्य से नहीं किया जाएगा। अतः, कथन 3 सही है।

80. Answer A
- The deposit insurance facility of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation is not available to depositors of NBFCs, unlike in the case of banks. Hence, statement 3 is not correct.
- All NBFCs are not entitled to accept public deposits. Only those NBFCs to which the Bank had given a specific authorization and have an investment grade rating are allowed to accept/ hold public deposits to a limit of 1.5 times its Net Owned Funds. Presently, the maximum rate of interest an NBFC can offer is 12.5%. The interest may be paid or compounded at rests not shorter than monthly rests. The NBFCs are allowed to accept/renew public deposits for a minimum period of 12 months and a maximum period of 60 months. They cannot accept deposits repayable on demand. Hence, statement 2 is not correct.

81. Answer B
- Kisan Credit Card Scheme was introduced by Indian banks in August 1998 in a bid to provide term loan for agricultural needs of the farmers.
- The model of KCC scheme was prepared by NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development) that met the recommendations of RV Gupta Committee.
- The premium under this scheme is borne by both the bank and borrower in a respective 2:1 ratio.

82. Answer A
- The primary goal of the scheme is to improve the health and well-being of women by replacing traditional and unhealthy cooking methods, such as using firewood or cow dung, with clean and efficient LPG.
- It is commonly known as the Ujjwala Scheme, is a government initiative launched by the Government of India in May 2016 in Ballia, Uttar Pradesh.
- It is implemented by the Union Ministry of Petroleum and Natural Gas.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

80. उत्तर ए
- डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की जमा बीमा सुविधा बैंकों के मामले के विपरीत, एनबीएफसी के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।
- सभी एनबीएफसी सार्वजनिक जमा स्वीकार करने के हकदार नहीं हैं। केवल वे एनबीएफसी जिन्हें बैंक ने एक विशिष्ट प्राधिकरण दिया है और जिनके पास निवेश ग्रेड रेटिंग है, उन्हें अपने शुद्ध स्वामित्व वाले फंड के 1.5 गुना की सीमा तक सार्वजनिक जमा स्वीकार करने/रखने की अनुमति है। वर्तमान में, एक एनबीएफसी अधिकतम 12.5% ब्याज दर की पेशकश कर सकता है। ब्याज का भुगतान या चक्रवृद्धि मासिक अंतराल से कम समय के अंतराल पर किया जा सकता है। एनबीएफसी को न्यूनतम 12 महीने और अधिकतम 60 महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक जमा स्वीकार/नवीनीकरण करने की अनुमति है। वे मांग पर चुकाने योग्य जमा स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

81. उत्तर बी
- किसानों की कृषि आवश्यकताओं के लिए सावधि ऋण प्रदान करने के लिए अगस्त 1998 में भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी।
- केसीसी योजना का मॉडल नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) द्वारा तैयार किया गया था जो आरवी गुप्ता समिति की सिफारिशों को पूरा करता था।
- इस योजना के तहत प्रीमियम बैंक और उधारकर्ता दोनों द्वारा संबंधित 2:1 अनुपात में वहन किया जाता है।

82. उत्तर ए
- योजना का प्राथमिक लक्ष्य पारंपरिक और अस्वास्थ्यकर खाना पकाने के तरीकों, जैसे कि जलाऊ लकड़ी या गाय के गोबर का उपयोग, को स्वच्छ और कुशल एलपीजी से बदलकर महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना है।
- इसे आमतौर पर उज्ज्वला योजना के रूप में जाना जाता है, यह भारत सरकार द्वारा मई 2016 में बलिया, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई एक सरकारी पहल है।
- इसे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

83. Answer B
Statement 3 is incorrect: C. Nachiket Mor recommended that each Indian resident, above the age of 18 years, would have an individual, safe and secure electronic bank account.

84. Answer B
- Statement 2 is incorrect: The maturity period of Certificates of Deposits can be more than a year if it is issued by All-India Financial Institutions.
- Big corporations with good credit rating issue commercial paper as a promissory note.
- The maturity period of Certificates of Deposits ranges from 7 days to 1 year, if issued by banks. The FIs can issue CDs for a period not less than 1 year and not exceeding 3 years from the date of issue.

85. Answer B
- Statement 2 is incorrect: The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 provides the legal basis for the setting up of ARCs in India.
- ARC is a specialized financial institution that buys the Non-Performing Assets (NPAs) from banks and financial institutions

86. Answer A
Explanation
• Ayushman Sahakar is a unique scheme to assist cooperatives to play an important role in the creation of healthcare infrastructure in the country formulated by the apex autonomous development finance institution under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, the
National Cooperative Development Corporation (NCDC). Hence statement 1 is not correct.
The scheme also provides working capital and margin money to meet operational requirements.The scheme provides interest subvention of one percent to women majority cooperatives. Hence Statement 3 is not correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

83. उत्तर बी
कथन 3 गलत है: सी. नचिकेत मोर ने सिफारिश की कि 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय निवासी के पास एक व्यक्तिगत, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक बैंक खाता होगा।

84. उत्तर बी
- कथन 2 गलत है: यदि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किया जाता है तो जमा प्रमाणपत्र की परिपक्वता अवधि एक वर्ष से अधिक हो सकती है।
- अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाले बड़े निगम वचन पत्र के रूप में वाणिज्यिक पत्र जारी करते हैं।
- यदि बैंकों द्वारा जारी किया जाता है, तो जमा प्रमाणपत्रों की परिपक्वता अवधि 7 दिन से 1 वर्ष तक होती है। वित्तीय संस्थाएं जारी होने की तारीख से कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए सीडी जारी कर सकती हैं।

85. उत्तर बी
कथन 2 गलत है: वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002 भारत में एआरसी की स्थापना के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।

एआरसी एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) खरीदता है

86. उत्तर ए
स्पष्टीकरण

- आयुष्मान सहकार देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सहकारी समितियों की सहायता के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत शीर्ष स्वायत्त विकास वित्त संस्थान द्वारा तैयार की गई एक अनूठी योजना है।
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- यह योजना परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी और मार्जिन मनी भी प्रदान करती है। यह योजना महिला बहुमत सहकारी समितियों को एक प्रतिशत की ब्याज छूट प्रदान करती है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

87. Answer: (d) 1, 2, 3, and 4

1. World Economic Outlook (IMF)

- Focus: Analyzes global financial stability and provides GDP growth forecasts.
- Update 2025: The report highlighted the "normalization" of inflation levels across G20 nations.
- Key Role: Acts as the primary guide for global investors regarding currency and interest rate trends.
- India Context: It projected India to remain the fastest-growing major economy at ~7%.
- Impact: Influences the sovereign credit ratings of developing nations.

2. World Trade Report (WTO)

- Focus: Examines the health of the multilateral trading system and trade barriers.
- Update 2025: Focused on "Digital Trade and AI," exploring how automation affects global supply chains.
- Key Role: Monitors the rise of protectionism and "friend-shoring" trends.
- Data Point: Reported a 5.2% growth in digitally delivered services globally.
- Impact: Used as a baseline for ministerial-level trade negotiations.

3. World Investment Report (UNCTAD)

- Focus: Tracks Foreign Direct Investment (FDI) flows and multinational enterprise activities.
- Update 2025: Analyzed the shift of FDI into Green Energy sectors in the Global South.
- Key Role: Identifies which countries are the most attractive destinations for foreign capital.
- Data Point: Highlighted that India remains among the top 5 recipients for Greenfield projects in 2024-25.
- Impact: Vital for policymakers to design Investment Treaties and Ease of Doing Business reforms.

4. Global Economic Prospects (World Bank)

- Focus: Deep-dives into the economic challenges of emerging and developing economies (EMDEs).
- Update 2025: Warned about the "Structural Slowdown" in potential growth for the next decade.
- Key Role: Provides specific regional outlooks (e.g., South Asia, Sub-Saharan Africa).
- Data Point: Noted that infrastructure gaps in developing nations require an additional $2.4 trillion annually.
- Impact: Guides the World Bank's lending and grant allocations for poverty alleviation.

87. उत्तर: (d) 1, 2, 3, और 4

1. विश्व आर्थिक परिदृश्य (आईएमएफ)

- फोकस: ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एनालिसिस करना और GDP ग्रोथ का अनुमान देना।
- अपडेट 2025: रिपोर्ट में G20 देशों में महंगाई के लेवल के "नॉर्मलाइज़ेशन" पर ज़ोर दिया गया।
- मुख्य भूमिका: करेंसी और इंटरेस्ट रेट ट्रेंड्स के बारे में ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए मुख्य गाइड के तौर पर काम करता है।
- भारत संदर्भ: इसमें अनुमान लगाया गया कि भारत ~7% की दर से सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा।
- असर: डेवलपिंग देशों की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग पर असर डालता है।

2. विश्व व्यापार रिपोर्ट (डब्ल्यूटीओ)

- फोकस: मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम की हेल्थ और ट्रेड बैरियर की जांच करना।
- अपडेट 2025: "डिजिटल ट्रेड और AI" पर फोकस, यह पता लगाना कि ऑटोमेशन ग्लोबल सप्लाई चेन को कैसे प्रभावित करता है।
- मुख्य भूमिका: प्रोटेक्शनिज़्म और "फ्रेंड-शोरिंग" ट्रेंड्स के बढ़ने पर नज़र रखना।
- डेटा पॉइंट: दुनिया भर में डिजिटली दी जाने वाली सेवाओं में 5.2% की बढ़ोतरी की रिपोर्ट की गई।
- असर: मिनिस्टीरियल लेवल की ट्रेड बातचीत के लिए बेसलाइन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

3. विश्व निवेश रिपोर्ट (UNCTAD)

- फोकस: फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) फ्लो और मल्टीनेशनल एंटरप्राइज एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है।
- अपडेट 2025: ग्लोबल साउथ में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में FDI के बदलाव का एनालिसिस किया गया।
- मुख्य भूमिका: यह पहचानना कि विदेशी पूंजी के लिए कौन से देश सबसे आकर्षक जगह हैं।
- डेटा पॉइंट: इस बात पर ज़ोर दिया गया कि भारत 2024-25 में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए टॉप 5 पाने वालों में बना हुआ है।
- असर: पॉलिसी बनाने वालों के लिए इन्वेस्टमेंट ट्रीटी और ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस सुधारों को डिज़ाइन करना ज़रूरी है।

4. वैश्विक आर्थिक संभावनाएं (विश्व बैंक)

- फोकस: उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDEs) की आर्थिक चुनौतियों पर गहराई से विचार करना।
- अपडेट 2025: अगले दशक में संभावित ग्रोथ में "स्ट्रक्चरल स्लोडाउन" के बारे में चेतावनी दी गई।
- मुख्य भूमिका: खास क्षेत्रीय नज़रिया देना (जैसे, दक्षिण एशिया, सब-सहारा अफ्रीका)।
- डेटा पॉइंट: ध्यान दें कि विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरा करने के लिए हर साल अतिरिक्त $2.4 ट्रिलियन की ज़रूरत होती है।
- असर: गरीबी हटाने के लिए वर्ल्ड बैंक के लोन और ग्रांट देने में गाइडेंस देता है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

88. Answer. B
Explanation.

'Public Distribution System' under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution is a system to ensure food security in India. Under the scheme, subsidized food and food items are distributed to the poor. It was started as a price support program. Food grains for the public distribution system are supplied by the Food Corporation of India (FCI). Which was established in the year 1965.

89. Answer C
Housing Finance Companies are regulated by the National Housing Bank, Merchant Banking Companies are regulated by the Securities and Exchange Board of India, and Insurance companies are regulated by the Insurance Regulatory and Development Authority. Hence, option C is correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

88. उत्तर.बी
स्पष्टीकरण।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक प्रणाली है। योजना के तहत गरीबों को सब्सिडी वाला भोजन और खाद्य सामग्री वितरित की जाती है। इसे मूल्य समर्थन कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा की जाती है। जिसकी स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी।

89. उत्तर सी
हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है, मर्चेंट बैंकिंग कंपनियों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है, और बीमा कंपनियों को बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। अतः, विकल्प C सही है।

90. Answer D
- An anti-dumping duty is a protectionist tariff that a domestic government imposes on foreign imports that it believes are priced below fair market value. Hence, statement 1 is not correct.
- CVDs are tariffs levied on imported goods to offset subsidies made to producers of these goods in the exporting country. Hence, statement 2 is not correct.

91. Answer A

When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector, because it forms the base for all other products that we subsequently make. Since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and allied sector.

The secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. It is the next step after primary. The product is not produced by nature but has to be made and therefore some process of manufacturing is essential. This could be in a factory, a workshop or at home.

92. Answer A

Tertiary sector economic activities, by themselves, do not produce a good but they are an aid or a support for the production process.

Transport, storage, communication, banking, trade are some examples of tertiary activities. Since these activities generate services rather than goods, the tertiary sector is also called the service sector.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

90. उत्तर D
- एंटी-डंपिंग शुल्क एक संरक्षणवादी टैरिफ है जो एक घरेलू सरकार विदेशी आयात पर लगाती है जिसके बारे में उसका मानना है कि उसकी कीमत उचित बाजार मूल्य से कम है। इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।
- सीवीडी निर्यातक देश में इन वस्तुओं के उत्पादकों को दी जाने वाली सब्सिडी की भरपाई के लिए आयातित वस्तुओं पर लगाए गए टैरिफ हैं। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

91. उत्तर ए
- जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके कुछ अच्छा उत्पादन करते हैं, तो यह प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, क्योंकि यह अन्य सभी उत्पादों के लिए आधार बनाता है जो हम बाद में बनाते हैं। चूँकि हमें अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मछली पकड़ने, वानिकी से प्राप्त होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि और संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है।
- द्वितीयक क्षेत्र उन गतिविधियों को शामिल करता है जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के तरीकों के माध्यम से अन्य रूपों में बदल दिया जाता है जिन्हें हम औद्योगिक गतिविधि से जोड़ते हैं। यह प्राइमरी के बाद अगला चरण है। उत्पाद प्रकृति द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता है बल्कि उसे बनाना पड़ता है और इसलिए विनिर्माण की कुछ प्रक्रिया आवश्यक है। यह किसी फ़ैक्टरी, वर्कशॉप या घर पर हो सकता है।

92. उत्तर ए
- तृतीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियाँ, अपने आप में, कोई अच्छा उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि वे उत्पादन प्रक्रिया के लिए एक सहायता या समर्थन हैं।
- परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, व्यापार तृतीयक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। चूँकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवाएँ उत्पन्न करती हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है।

93. Answer B

Over the time, the contribution of the Tertiary sector to India's GDP has increased, in comparison to the primary and secondary sector. While production in the service sector rose by 11 times, employment in the service sector rose less than three times. The primary sector continues to be the largest employer. It is because not enough jobs were created in the secondary and tertiary sectors. As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only a quarter of the GDP. In contrast to this, the secondary and tertiary sectors produce three-fourth of the produce whereas they employ less than half of the people.

94. Answer: B

Explanation

● Statement 1 is incorrect. Phillips curve chalks out an inverse relationship between inflation rate and rate of unemployment. It emphasizes on a trade-off relationship between inflation and unemployment. Thus, a certain level of inflation is desirable in an economy to ensure development.

95. Answer C

Pent-up demand refers to a situation where demand for a service or product is unusually strong. Pent-up demand describes a rapid increase in demand for a service or product, usually following a period of subdued spending. Hence statement II is not correct.

Consumers tend to hold off making purchases during a recession, building up a backlog of demand that is unleashed when signs of a recovery emerge.

Pent-up demand is especially evident with big-ticket, durable goods. When economic times get tough, consumers tend to refrain from making expensive, big-ticket purchases such as vehicles, appliances, and other durable goods, instead opting to make what they have lasted longer—even if it requires extra maintenance and repairs. Once conditions improve, there is a surge in spending. Hence statement I is correct.

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

93. उत्तर बी

- समय के साथ, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की तुलना में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ गया है। जबकि सेवा क्षेत्र में उत्पादन 11 गुना बढ़ गया, सेवा क्षेत्र में रोजगार तीन गुना से भी कम बढ़ गया। प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता बना हुआ है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में पर्याप्त नौकरियाँ पैदा नहीं हुईं।
- परिणामस्वरूप, देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मुख्य रूप से कृषि में, जो सकल घरेलू उत्पाद का केवल एक चौथाई उत्पादन कर रहे हैं। इसके विपरीत, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र तीन-चौथाई उत्पादन करते हैं जबकि वे आधे से भी कम लोगों को रोजगार देते हैं।

94. उत्तर: B

स्पष्टीकरण

- कथन 1 गलत है। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी की दर के बीच एक विपरीत संबंध बताता है। यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक व्यापारिक संबंध पर जोर देता है। इस प्रकार, किसी अर्थव्यवस्था में विकास सुनिश्चित करने के लिए मुद्रास्फीति का एक निश्चित स्तर वांछनीय है।

95. उत्तर सी

- दबी हुई मांग उस स्थिति को संदर्भित करती है जहां किसी सेवा या उत्पाद की मांग असामान्य रूप से मजबूत होती है। दबी हुई मांग किसी सेवा या उत्पाद की मांग में तेजी से वृद्धि का वर्णन करती है, जो आमतौर पर कम खर्च की अवधि के बाद होती है। अतः कथन II सही नहीं है।
- उपभोक्ता मंदी के दौरान खरीदारी करना बंद कर देते हैं, जिससे मांग का बैकलॉग तैयार हो जाता है, जो सुधार के संकेत मिलने पर सामने आता है।
- दबी हुई मांग विशेष रूप से बड़े-टिकट वाले, टिकाऊ सामानों के साथ स्पष्ट है। जब आर्थिक समय कठिन हो जाता है, तो उपभोक्ता वाहन, उपकरण और अन्य टिकाऊ सामान जैसी महंगी, बड़ी खरीदारी करने से बचते हैं, इसके बजाय वे वही बनाते हैं जो लंबे समय तक चलता है - भले ही इसके लिए अतिरिक्त रखरखाव और मरम्मत की आवश्यकता हो। एक बार हालात बेहतर होने पर खर्च में बढ़ोतरी हो जाती है। अतः कथन I सही है।

96. Answer A

- Statement 2 is incorrect: Presently, in India, identification of the poor is done by the State Governments based on information from Below Poverty Line (BPL) censuses of which the latest is the Socio Economic Caste Census 2011 (SECC 2011).
- Statement 3 is incorrect: Poverty line should vary over regions mainly because of the variations of the tastes and preferences and the price structures over the regions.
- Hence, determining components of Poverty Line Basket (PLB) has been one of the key challenges of poverty line estimation in India due to price differentials (of constituents of basket) which vary from state to state and period to period.

97. Answer C

Automotive Mission Plan 2026 has been finalized jointly by the Government of India and the Indian Automotive Industry. Hence, statement 1 is correct.

The AMP 2026 is aimed at bringing the Indian Automotive Industry among the top three of the world in engineering, manufacturing, and exports of vehicles & components; growing in value to over 12% of India's GDP and generating an additional 65 million jobs. Hence, statement 2 is correct.

It envisages implementing the End of Life Policy for automotive vehicles and components. Hence, statement 3 is correct.

96. उत्तर ए

- कथन 2 गलत है: वर्तमान में, भारत में, गरीबों की पहचान राज्य सरकारों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जनगणनाओं की जानकारी के आधार पर की जाती है, जिनमें से नवीनतम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 (एसईसीसी 2011) है।
- कथन 3 गलत है: गरीबी रेखा अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग होनी चाहिए, इसका मुख्य कारण अलग-अलग क्षेत्रों में स्वाद और प्राथमिकताओं और मूल्य संरचनाओं में भिन्नता है।
- इसलिए, मूल्य अंतर (टोकरी के घटकों) के कारण गरीबी रेखा बास्केट (पीएलबी) के घटकों का निर्धारण भारत में गरीबी रेखा के आकलन की प्रमुख चुनौतियों में से एक रहा है, जो राज्य दर राज्य और समय दर अवधि में भिन्न होता है।

97. उत्तर सी

- ऑटोमोटिव मिशन योजना 2026 को भारत सरकार और भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से अंतिम रूप दिया गया है। अतः, कथन 1 सही है।
- एएमपी 2026 का उद्देश्य भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को इंजीनियरिंग, विनिर्माण और वाहनों और घटकों के निर्यात में दुनिया के शीर्ष तीन में लाना है; भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 12% से अधिक मूल्य में वृद्धि और अतिरिक्त 65 मिलियन नौकरियां पैदा करना। अतः, कथन 2 सही है।
- इसमें ऑटोमोटिव वाहनों और घटकों के लिए जीवन समाप्ति नीति को लागू करने की परिकल्पना की गई है। इसलिए, कथन 3 सही है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations

98. Answer C

A higher credit-to-GDP ratio indicates aggressive and active participation of the banking sector in the real economy, while a lower number shows the need for more formal credit. Hence statement 2 is correct.

Basel III introduced a countercyclical capital buffer (CCB) aimed at strengthening banks' defenses against the build-up of systemic vulnerabilities. The framework assigns the credit-to-GDP gap a prominent role as a guide for policymakers. The guide is intended to help frame the analysis of whether to activate or increase the required buffer and the communication of the related decisions. Hence statement 1 is correct.

99. Answer B

The government's thrust on CAPEX, particularly in the infrastructure-intensive sectors like roads and highways, railways, and housing and urban affairs, has longer-term implications for growth as it enhances the productive capacity of an economy in the long run. Hence, statement 1 is correct.

The government's emphasis on capital expenditure provides a boost to private investment due to a decrease in interest rate (crowding in private investment). Crowding out effect, on the other hand, refers to the situation when increased interest rates lead to a reduction in private investment spending such that it dampens the initial increase of total investment spending. Hence, statement 2 is not correct.

Capital expenditure provides a boost to Aggregate Demand (AD) by giving a boost to Private consumption (C), Investment (I), and Government expenditure (G) components. (AD = C+I+G). Hence, statement 3 is correct.

100. Answer B

Zero-Coupon Bonds: Zero-Coupon Bonds are issued at a discount and redeemed at par. No interest payment is made on such bonds at periodic intervals before maturity. On the basis of the bids received through tenders, the Reserve Bank of India will determine the cut-off price at which tenders for the purchase of Zero Coupon Bonds will be accepted at the auction. Hence, statement 2 is not correct.

98. उत्तर सी

- उच्च क्रेडिट-टू-जीडीपी अनुपात वास्तविक अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र की आक्रामक और सक्रिय भागीदारी को इंगित करता है, जबकि कम संख्या अधिक औपचारिक ऋण की आवश्यकता को दर्शाती है। अतः कथन 2 सही है।
- बेसल III ने प्रणालीगत कमजोरियों के निर्माण के खिलाफ बैंकों की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एक प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीबी) की शुरुआत की। यह रूपरेखा नीति निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में क्रेडिट-टू-जीडीपी अंतर को एक प्रमुख भूमिका प्रदान करती है। गाइड का उद्देश्य आवश्यक बफर को सक्रिय करने या बढ़ाने और संबंधित निर्णयों के संचार के विश्लेषण में मदद करना है। अतः कथन 1 सही है।

99. उत्तर बी

- CAPEX पर सरकार का जोर, विशेष रूप से सड़क और राजमार्ग, रेलवे और आवास और शहरी मामलों जैसे बुनियादी ढांचे-गहन क्षेत्रों में, विकास के लिए दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह लंबे समय में अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है। अतः, कथन 1 सही है।
- पूंजीगत व्यय पर सरकार का जोर ब्याज दर में कमी (निजी निवेश में भीड़) के कारण निजी निवेश को बढ़ावा देता है। दूसरी ओर, क्राउडिंग आउट प्रभाव उस स्थिति को संदर्भित करता है जब बढ़ी हुई ब्याज दरों के कारण निजी निवेश खर्च में कमी आती है, जिससे कुल निवेश खर्च की प्रारंभिक वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।
- पूंजीगत व्यय निजी उपभोग (सी), निवेश (आई), और सरकारी व्यय (जी) घटकों को बढ़ावा देकर समग्र मांग (एडी) को बढ़ावा देता है। (एडी = सी+आई+जी)। अतः, कथन 3 सही है।

100. उत्तर बी

- जीरो-कूपन बांड: जीरो-कूपन बांड छूट पर जारी किए जाते हैं और बराबर मूल्य पर भुनाए जाते हैं। ऐसे बांडों पर परिपक्वता से पहले आवधिक अंतराल पर कोई ब्याज भुगतान नहीं किया जाता है। निविदाओं के माध्यम से प्राप्त बोलियों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक कट-ऑफ मूल्य निर्धारित करेगा जिस पर शून्य कूपन बांड की खरीद के लिए निविदाएं नीलामी में स्वीकार की जाएंगी। इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।

RACE IAS General Studies Rajesh Academy for Civil Examinations